हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 266 बेमेतरा, शनिवार 23 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशक की ओर से 19 मई को जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश बंगाल में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मदरसों पर लागू होगा। आदेश के मुताबिक, कक्षाओं के शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी में जारी एक निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम के प्रचलन से पहले, छात्र सुबह की सभा में रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन-गण-मन गाते हैं।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की कैबिनेट का विस्तार

चेन्नई। तमिलनाडु में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति विजय (सी जोसेफ विजय) ने गुरुवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए 23 मंत्रियों को शामिल किया। इसमें मंत्री बनने वाले 19 विधायक तमिलगा वेट्टी कजगम (टीवीके), जबकि 2 विधायक सहयोगी कांग्रेस पार्टी के हैं। फिलहाल, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के लिए 2 मंत्री पद रिक्त रखे गए हैं। विधायकों ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री विजय की उपस्थिति में मंत्री पद की शपथ ली। गुरुवार को शपथ लेने वाले टीवीके विधायकों में श्रीनाथ, कमली एस, सी विजयलक्ष्मी, आरवी रंजीतकुमार, विनोथ, राजीव, बी राजकुमार, वी गांधीराज, मथन राजा पी, जेगदेश्वरी के, राजेश एस, एम विजय बालाजी, लोगेश तमिलसेल्वन डी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अल जफजिया जहाज को गुजरात के शिपयार्ड में ले जाने की इजाजत दी

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरकार अल जफजिया जहाज को गुजरात के अलंग शिप डंपयार्ड में ले जाने की इजाजत दे दी है. यह जहाज फ्यूल चोरी और बिटुमेन स्मगलिंग केस में कार्रवाई के दायरे में आए तीन जहाजों में से एक है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारतीय तटरक्षक (इंडियन कोस्ट गार्ड) और दूसरे संबंधित विभागों से सभी जरूरी पूर्व अनुमति ली जाए. कोस्ट गार्ड ने फरवरी में भारतीय जलक्षेत्र में तीन जहाजों एमटी एस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रूबी और एमटी अल जफजिया को रोका था. इसके बाद, उन्हें येलो गेट पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया गया.

भारत-साइप्रस के बीच द्विपक्षीय वार्ता

पीएम मोदी बोले-समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंध

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत और साइप्रस के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती न केवल मजबूत है, बल्कि भविष्य की जरूरतों और संभावनाओं के अनुरूप भी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय की कसौटी पर बार-बार खरे उतरे हैं और अब इन्हें नई दिशा देने के लिए रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष साइप्रस यात्रा के दौरान उन्हें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान को भारत कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि साइप्रस द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की साझेदारी लोकतंत्र, कानून के शासन और संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के चलते कई नई आर्थिक संभावनाएं खुली हैं और भारत अगले पांच वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, भारत शांति और संघर्षों के जल्द समाधान के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। साथ ही उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा, नई महत्वाकांक्षा और नई गति लेकर आएगी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने कहा कि उनका मुख्य फोकस भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिडेस ने कहा कि मैं आज यहां केवल साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ के उस सदस्य देश के प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद हूं।

प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर सहमति

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, हमने 'प्रवासन और गतिशीलता समझौते'और 'सामाजिक सुरक्षा समझौते' पर सहमति बनाई है। हम उच्च शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी समझौते कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद से जुड़े मामले पर कहा, साइप्रस के साथ हमारा रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हमने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

इससे पहले दिन में राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिड्स ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलिड्स से मुलाकात की और भारत-साइप्रस संबंधों और भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को लेकर उनके सकारात्मक विचारों की सराहना की। बैठक के बाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, नई दिल्ली में साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स से मिलकर बहुत खुशी हुई।

तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट!

एक साथ 31 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अदरूनी कलह सामने आई है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने नतीजों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक नदारद रहे। इसके साथ गी दो नगरपालिकाओं में टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर बगावती रूख अपना लिया। इससे अब तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ने की अटकलें तेज हो गई है।पश्चिम बंगाल में विधानसभा परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर

की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस धरने में टीएमसी पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 36 विधायक ही शामिल हुए। विधायकों ने ऐसे समय में बगावत की है, जब टीएमसी खुद को एक बार फिर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी कालीघाट में 19 मई को पार्टी की बैठक हुई थी। इसमें भी 15 के करीब विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। इसी बीच टीएमसी के 31 पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे की चर्चाओं ने माहौल गरम कर दिया है। उत्तर 24 परगना जिले की कांचरापाड़ा और हलीशहर नगरपालिकाओं में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। कांचरापाड़ा नगरपालिका में टीएमसी के 24 पार्षद है, इनमें से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं, हलीशहर नगरपालिका में टीएमसी के 23 में पार्षदों में से 16 पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपना पद छोड़ दिया।

पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर मतदान जारी, टीएमसी उम्मीदवार के पीछे हटने से मुकाबला कड़ा

दक्षिण। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। यहां के 285 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और वोटों की गिनती 24 मई को होगी। सीट पर लगभग 1.15 लाख महिलाएं और 9 तृतीय-लिंगी मतदाताओं सहित 2.36 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाली इस सीट पर 29 अप्रैल को बंगाल के दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था।

दिल्ली दंगा मामला

उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। यह निर्णय उनकी मां की सर्जरी के कारण लिया गया। अदालत ने 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए जमानत मंजूर की। इसके लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ही रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें घर पर रहना होगा और केवल अस्पताल जाने की अनुमति होगी। न्यायालय ने पहले भी खालिद को पारिवारिक समारोहों के लिए जमानत दी थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था। अदालत ने उन्हें मामले में मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक बताया। हालांकि, मां की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए सीमित अंतरिम राहत दी गई। दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। आक्रोशित लोगों ने केंद्र सरकार के फैसलों-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए थे।

घुसपैठियों को बाहर करने की शून्य-सहिष्णुता नीति

अमित शाह ने 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना की घोषणा की

नई दिल्ली/ एजेंसी

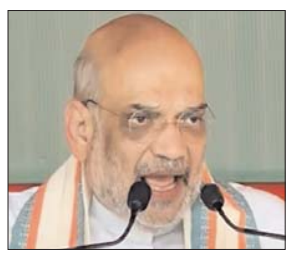

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की कि सरकार सीमा पार घुसपैठ के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। उन्होंने बताया कि देश की सीमाओं को सील करने और सभी अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए एक व्यापक स्मार्ट बॉर्डर परियोजना इस वर्ष शुरू की जाएगी। शाह ने कहा कि अवैध प्रवासन जनसांख्यिकीय बदलाव लाने की एक सोची-समझी साजिश है, और सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे निर्वासित करेगी। विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पदग्रहण समारोह 2026 को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही। गृह मंत्रालय देश की 6,000 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एक अभेद्य सुरक्षा ग्रिड लागू करेगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले एक वर्ष के भीतर, स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत, बीएसएफ को ड्रोन रडार और उन्नत कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह मंत्री ने बीएसएफ से आग्रह किया कि वह घुसपैठ और पशु तस्करी के मार्गों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए राज्य पुलिस, जिला कलेक्टरों और ग्राम पटवारियों के साथ सीधे समन्वय करके अपने खुफिया नेटवर्क का विस्तार करे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सरकारों के साथ नीतिगत तालमेल इस सुरक्षा ग्रिड को सुविधाजनक बनाएगा।

राहुल गांधी बोले- मोदी का मेलोडी रील हर भारतीय का अपमान

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बनाए गए मेलोडी रील पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमला जारी है। उन्होंने एक्स पर अपना एक वीडियो साझा कर लिखा कि मोदी जी, आपका मेलोडी रील हर भारतीय का और उसके दर्द का अपमान है। इससे पहले भी राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के मेलोडी रील पर लिखा था कि सब रो रहे हैं और प्रधानमंत्री टॉफी बांट रहे हैं, जो नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। राहुल ने वीडियो में कहा, हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल, पेट्रोल-डीजल और विमान ईंधन के दाम आसमान को छुएंगे। खाद की कमी होगी ।

सीएम साय बोले यह सुशासन का प्रमाण

छत्तीसगढ़ के उसूर ब्लॉक को मिला दूसरा स्थान.....

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 'सुशासन' और जन कल्याणकारी नीतियों का असर अब राज्य के सबसे दूरस्थ अंचलों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले से एक गौरवशाली खबर सामने आई है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों की 'चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर' (अक्टूबर- दिसंबर 2025) की रिपोर्ट में बीजापुर के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर उसूर ब्लॉक और बीजापुर जिले के नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा, उसूर ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करना हमारे सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस्तर के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उसूर ने कठिन परिस्थितियों में जो कर दिखाया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। यह सफलता जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिन बहनों, एएनएम और डॉक्टरों के समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य अब देश में प्रथम स्थान हासिल करना है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में उसूर ब्लॉक की यह राष्ट्रीय सफलता बेहद गौरवशाली है।

दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 सिर्फ भारत के!

भारत में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा....टूट रहे सारे रिकॉर्ड....

नई दिल्ली/ एजेंसी

सड़कें तप रही थीं, धातु की रेलिंग को छूना भी मुश्किल हो गया था, और मौसम पर नज़र रखने वाले बार-बार एक ही पैटर्न दिखा रहे हैं — भारतीय शहर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। पिछले हफ़्ते दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 99 शहरों के साथ टॉप पर रहने के बाद भारत ने गुरुवार को फिर से 100 में से 97 शहरों के साथ टॉप पर अपनी जगह बनाई है। लाइव ग्लोबल तापमान रैंकिंग एजेंसी AQI ने इस हफ़्ते दिखाया कि दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म स्थानों में भारतीय शहरों की असाधारण मौजूदगी जारी है, जो देश को अपनी चपेट में ले रही लू की तीव्रता को दिखाता है। 22 मई को दोपहर 2:49 बजे तक के लाइव डेटा के अनुसार, 100 शहरों में से तीन नेपाल के हैं, जबकि 97 भारत के हैं। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के शहर रैंकिंग में टॉप पर रहे। ओडिशा का बलांगीर, बिहार का सासाराम और कका वाराणसी दुनिया के तीन सबसे गर्म स्थानों में शामिल थे, जहाँ हर जगह तापमान लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी लिस्ट के टॉप 50 में शामिल थे, क्योंकि झुलसा देने वाली हवाओं और सूखे मौसम की वजह से गर्मी और बढ़ गई थी। सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश रैंकिंग में सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, जहाँ प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ग़ाज़ीपुर, बांदा और फ़तेहपुर जैसे शहरों में दिन का तापमान बार-बार बहुत ज़्यादा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र इसके ठीक पीछे है, खासकर विदर्भ क्षेत्र के शहरों जैसे चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा और अमरावती की वजह से। छत्तीसगढ़ भी प्रमुखता से शामिल है, जहाँ रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग देश के सबसे गर्म शहरी केंद्रों में से हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी ज़िलों से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के गर्मी से बेहाल हिस्सों तक, तापमान इतनी तेज़ी से और लगातार बढ़ा है जितना इस मौसम में इतनी जल्दी शायद ही कभी देखा गया हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भीषण गर्मी की स्थिति दर्ज की गई, जबकि ओडिशा के बालांगीर और राउरकेला में साफ़ आसमान के नीचे दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहा। इनमें से ज़्यादातर शहरों में मौसम की स्थिति को लाइव रैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा बेहद गर्म के रूप में चिह्नित किया गया। जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गर्मी की ये भीषण लहरें अब ज़्यादा बार आ रही हैं, और ज़्यादा बड़े इलाके में फैल रही हैं।

11 से 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह

राज्य के अधिकारियों ने लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि उन घंटों के दौरान हिटवेव और बहुत ज्यादा तापमान अपने पीक पर होता है। भारत के मौसम विभाग ने 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में 'लू से लेकर बहुत ज्यादा लू' चलने का अनुमान लगाया है। तेज गर्मी की वजह से देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में डायरिया और डिहाइड्रेशन से परेशान मरीजों की लंबी लाइनें लग गई हैं। वहीं, पश्चिमी राज्य गुजरात में पानी की कमी की खबरें आई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के विजुअल्स में यह बात सामने आई है।

तेज गर्मी के कारण बढ़ रही बीमारियां

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबकि, मार्च की शुरुआत से मई के बीच गर्मी से जुड़ी बीमारियों के 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 1 मार्च से 19 मई के बीच हीटस्ट्रोक के 325 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग एक तिहाई मई की शुरुआत से रिपोर्ट किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हीटस्ट्रोक, शरीर के ज्यादा गर्म होने से होने वाली एक मेडिकल इमरजेंसी है, अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो इससे कन्फ्यूजन, चक्कर आना, जी मिचलाना, दौरे पड़ना, बेहोशी और ऑर्गन फेलियर हो सकता है।

भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की अपील, जिला अस्पताल में विशेष लू-वार्ड तैयार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी एवं ग्रीष्म लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला चिकित्सालय बेमेतरा द्वारा आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने तथा लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. लोकेश साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नवतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को बेमेतरा जिले में तेज गर्म हवाओं और झुलसा देने वाली धूप ने जनजीवन को प्रभावित किया। जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि रात के समय भी गर्म हवाएं चलती रहीं। दोपहर में स्थिति इतनी गंभीर रही कि कूलर भी ठंडी हवा देने में असफल रहे। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बेमेतरा सहित बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा राजनांदगांव जिलों में ग्रीष्म लहर की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बेमेतरा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में भी हीटवेव की संभावना जताई गई है।

दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर न निकलने की अपील-डॉ. लोकेश साहू ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। यदि बाहर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें तथा पूरे शरीर को ढंककर रखें। धूप से बचाव के लिए छाता, टोपी, गमछा एवं धूप के चश्मे का उपयोग करें।

लू से बचाव के लिए बरतें ये सावधानियां-पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ लें, प्यास न लगने पर भी समय-समय पर पानी पीते रहें। ओआरएस, नींबू पानी, छाछ एवं नारियल पानी का सेवन करें। अत्यधिक चाय, कॉफी एवं शराब के सेवन से बचें। ताजा फल एवं हल्का भोजन लें। बासी, तला-भुना और अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। बच्चों, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं का रखें विशेष ध्यान 7 बच्चों या पशुओं को बंद वाहन में अकेला न छोड़ें। बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को तेज धूप से बचाकर रखें। धूप में कार्य करने वाले श्रमिक समय-समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करें तथा नियमित अंतराल में पानी पीते रहें।

लू लगने के प्रमुख लक्षण-स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तेज बुखार, चक्कर आना, बेहोशी, अत्यधिक कमजोरी, घबराहट, तेज धड़कन एवं सांस लेने में कठिनाई लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं।

हीट स्ट्रोक की स्थिति में तुरंत करें ये उपाय-यदि किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसे तुरंत ठंडी एवं छायादार जगह पर ले जाएं। शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी करें। मरीज के होश में होने पर उसे पानी या ओआरएस पिलाएं तथा तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय बेमेतरा पहुंचाएं।

जिला अस्पताल में विशेष लू-वार्ड तैयार-डॉ. लोकेश साहू ने बताया कि जिला चिकित्सालय बेमेतरा में लू से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए विशेष लू-वार्ड तैयार किया गया है। अस्पताल में ओआरएस, आईवी फ्लूड एवं आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सुरक्षित रहें तथा आसपास के लोगों को भी गर्मी एवं लू से बचाव के प्रति जागरूक करें।

अनुकम्पा नियुक्ति के तहत श्रीमती सुनीता जांगड़े को मिली भृत्य पद पर नियुक्ति

तहसील कार्यालय बेमेतरा में दी गई पदस्थापना, 3 वर्ष की रहेगी परिवीक्षा अवधि

बेमेतरा, 22 मई 2026:- राज्य शासन के निर्देशों एवं आयुक्त दुर्ग संभाग से प्राप्त अनुमति के पश्चात दिवंगत शासकीय सेवक स्वर्गीय श्री सुभाष जांगड़े की पत्नी सुनीता जांगड़े को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उन्हें तहसील कार्यालय बेमेतरा में रिक्त भृत्य पद पर पदस्थ किया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्रीमती सुनीता जांगड़े, ग्राम एवं पोस्ट झाल, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा निवासी हैं। उन्हें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-01 के अंतर्गत 15,600 रुपये से 49,400 रुपये प्रतिमाह वेतनमान तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों का लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

3 वर्ष की होगी परिवीक्षा अवधि-आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति प्रारंभिक रूप से अस्थायी होगी तथा उनकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्वास्थ्य एवं चरित्र सत्यापन अनिवार्य-कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल जानकारी पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा आवश्यक-नियुक्ति आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यभार ग्रहण करते समय सभी मूल प्रमाण-पत्र परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उनकी छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी तय-अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने वाली आवेदिका को दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि भविष्य में यह प्रमाणित होता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश-आदेशानुसार नियुक्त आवेदिका को पदस्थ कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के बाद किसी अन्य पद पर परिवर्तन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

'जल-जंगल-जमीन बचाने छत्तीसगढ़िया होवव एकजुट' – रजकुड़ी खड़ म गूंजिस छत्तीसगढ़ियावाद के हुंकार, 50 नए सदस्य जुड़िन

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संयुक्त बैठक में संगठन विस्तार,

छत्तीसगढ़िया अस्मिता और जनअधिकार के मुद्दा पर हुए अहम चर्चा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बेमेतरा की संयुक्त बैठक दिनांक 21 मई 2026, गुरुवार को ग्राम रजकुड़ी, जिला बेमेतरा में उत्साह एवं जोशपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवा, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ियावाद, जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा, सामाजिक अधिकार, स्थानीय युवाओं के भविष्य एवं संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान चलाए जा रहे जबर सदस्यता अभियान के अंतर्गत 50 नए सदस्यों ने छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा एवं छत्तीसगढ़िया अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना के जिलाध्यक्ष निलेश कुमार साहू, खड़ अध्यक्ष लुकेश्वर साहू, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के शहर अध्यक्ष फौजी सूर्या सिंह चौहान एवं उपाध्यक्ष खेमू साहू की विशेष उपस्थिति रही। अपने ओजस्वी संबोधन में जिलाध्यक्ष निलेश कुमार साहू ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार बाहरी शक्तियों की नजर बनी हुई है। यदि छत्तीसगढ़िया समाज समय रहते संगठित एवं जागरूक नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ियों को अपनी ही माटी में संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अब समय केवल तमाशा देखने का नहीं, बल्कि अपने अधिकार एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होने का है। वहीं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के शहर अध्यक्ष फौजी सूर्या सिंह चौहान ने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं, किसानों एवं आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है। बेरोजगारी, पलायन, किसानों की समस्याएं एवं स्थानीय मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। उपाध्यक्ष खेमू साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में जागरूक छत्तीसगढ़िया युवा एवं नागरिक संगठन से जुड़ रहे हैं, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ियावाद की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। खड़ अध्यक्ष लुकेश्वर साहू ने भी संगठन की मजबूती एवं गांव स्तर पर जनजागरण अभियान को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया समाज को अपनी भाषा, संस्कृति एवं अधिकारों की रक्षा के लिए अब संगठित होकर आगे आना होगा।बैठक के अंत में संगठन विस्तार, आगामी जनजागरण अभियान एवं सदस्यता अभियान को और तेज गति से चलाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी के जयघोष के साथ छत्तीसगढ़िया एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। उक्त जानकारी खेमू साहू शहर उपाध्यक्ष जेसीपी बेमेतरा ने प्रेस विज्ञप्ति की माध्यम से दिया।

श्रीकृष्ण गौशाला चांपा में शीघ्र होगी गौ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

चांपा/मूक पत्रिका

गौ माता के संवर्धन, संरक्षण,चिकित्सा,पंचगव्य प्राप्ति हेतु गौ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु शुक्रवार 22 मई को छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल ने गौशाला में अनुसंधान केंद्र की संभावित स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने श्रीकृष्ण गौशाला चांपा में गौ अनुसंधान करने पंचगव्य निर्माण, अहाता निर्माण, गौ अनुसंधान केंद्र में गौ पालन एवं संरक्षण,नस्ल सुधार,संवर्धन के गौ माता के गोबर और गोमूत्र पर आधारित उत्पादों से प्राप्त होने वाली पंचगव्य का परिशोधन कर विस्तृत अनुसंधान के माध्यम से पंचगव्य से निर्मित औषधियों के निर्माण के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी पंचगव्य की महत्ता को स्थापित करने एवं प्रशिक्षण के माध्यम से गौ पालन में जन - जन को जागरूक करने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही पटेल ने उच्चाधिकारियों को गौ सेवा हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। ज्ञात हो कि गौ अनुसंधान केंद्र की मांग को लेकर भाजपा नेता एवं पूर्व राज्य सभा सांसद प्रतिनिधि अखिलेश कोमल पांडेय ने बिलासपुर प्रवास के दौरान विगत दिनों विशेषर पटेल से सौजन्य भेंटकर ज्ञापन सौपा था। पूर्व राज्य सभा सांसद एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार साय की सांसद निधि से 10 लाख रुपए की लागत से श्री कृष्ण गौशाला चांपा में नवीन गौशाला भवन का निर्माण हुआ था। इसी तारतम्य में गौ अनुसंधान केंद्र की बहुप्रतीक्षित मांग अब साकार होती नजर आ रहा है। भाजपा नेता अखिलेश कोमल पाण्डेय ने बताया कि गौशाला में नवीन भवन , शेड,बाऊंड्रीवाल एवं सौर ऊर्जा का शीघ्र ही निर्माण किया जाएगा,जिससे गौ वंश को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सकेगा। नवीन भवन, शेड के निर्माण होते ही गौशाला में गौवंश की वृद्धि कर विधिवत अनुदान प्राप्ति के साथ ही पंचगव्य तथा अनुसंधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

बेरला ब्लॉक में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का चुनाव/मनोनयन कार्यक्रम 24 मई दिन रविवार को

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला बेमेतरा द्वारा बेरला ब्लॉक के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के चुनाव एवं मनोनयन कार्यक्रम का आयोजन 24 मई 2026, दिन रविवार को किया जाएगा। कार्यक्रम सतनाम भवन बेरला में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन केवल चुनाव प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की एकता, जागरूकता और भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में समाज के अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी वर्ग एवं सभी सम्माननीय समाजजनों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील की गई है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री एल.एल. कोशले उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री राजालाल बंजारे करेंगे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में श्री गुलाबदास टंडन एवं श्री भुवन दास जांगड़े शामिल होंगे। आयोजकों ने कहा कि समाज की मजबूती, शिक्षा, व्यापार, सामाजिक सम्मान एवं संगठन विस्तार के लिए सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी समाजजनों से उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

बिजली संकट पर उबाल: अध्यक्ष प्रदीप नामदेव के नेतृत्व में पार्षद व मोहल्लेवासी पहुँचे बिजली कार्यालय

चांपा/मूक पत्रिका

वार्ड क्रमांक 2 में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज़ नागरिकों का गुस्सा शुक्रवार को खुलकर सामने आ गया। आज सुबह 11 बजे नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप नामदेव के नेतृत्व में पार्षदों एवं बड़ी संख्या में मोहल्लेवासियों ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।इस दौरान पार्षद श्रीमती गीता सूर्यप्रकाश कंसारी, महेंद्र तिवारी, राजन गुप्ता और राजीव नयन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में वार्ड क्रमांक 2 में बार-बार हो रही बिजली गुल की समस्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।पार्षद गीता सूर्यप्रकाश कंसारी ने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में दिन में कई बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति, पंखा, कूलर सहित दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है।नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप नामदेव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही वार्ड क्रमांक 2 की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई, तो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।वार्डवासियों ने भी विद्युत विभाग से मांग की है कि गर्मी के इस कठिन समय में निर्बाध एवं नियमित बिजली आपूर्ति की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। नागरिकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि समस्या जस की तस बनी रही, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। उल्लेखनीय हैं कि नगर के अनेक वार्डों में विशेष कर सदर बाजार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में राधा कृष्ण मंदिर फीडर एरिया भी बिजली की आवाजाही से निरंतर प्रभावित है।वार्डवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में आयदिन कई-कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती है जबकि मौसम की कोई खराबी नही होती।वार्डवासियों का कहना है कि विगत माह मेंटेनेंस के नाम पर दो बार फीडर की विद्युत आपूर्ति मंडल द्वारा चार-चार घँटे की अवधि के लिए बाधित की गई है,बावजूद इसके भीषण गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद होने से उन्हें गर्मी के अलावा विद्युत चलित उपकरण बंद होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में शीघ्र आवश्यक सुधार कर निर्बाध्य विद्युत आपूर्ति बहाल नही की गई तो उनके द्वारा मंडल के खिलाफ शीघ्र बढ़ा आंदोलन किया जाएगा।जिसकी जिम्मेदारी पूर्णरूपेण विद्युत मंडल की होगी।

पश्चिम एशिया संकट के बीच राज्य सरकार सतर्क, पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू, बोतल-ड्रम में विक्रय पर रोक

उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट और उसके संभावित प्रभावों को देखते हुए राज्य शासन ने पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री और वितरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल केवल सीधे उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकियों में ही दिया जाएगा। ड्रम, बोतल अथवा जेरीकेन में ईंधन विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा समानांतर विपणनकर्ता कंपनियों के सभी रिटेल आउटलेट संचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। शासन के अनुसार ड्रम, बोतल या जेरीकेन में पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री को मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत ÷अप्राधिकृत विक्रय÷ माना जाएगा।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई-राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जमाखोरी या अनियमित वितरण की स्थिति उत्पन्न न हो।

किसानों और आवश्यक सेवाओं को दी गई राहत-राज्य शासन ने रबी सीजन की फसल कटाई तथा आगामी खरीफसीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को इस व्यवस्था से आंशिक छूट प्रदान की है। इसके अलावा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण जैसे समय-सीमा वाले शासकीय कार्यों तथा अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को भी प्रतिबंध से राहत दी गई है। इन श्रेणियों के लिए आवश्यकता अनुसार डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा, ताकि कृषि कार्यों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

एसडीएम की अनुमति के बाद मिलेगा ईंधन-शासन के निर्देशानुसार कृषकों, शासकीय निर्माण कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ईंधन वितरण की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा मांग के परीक्षण के बाद दी जाएगी। अनुमति मिलने के उपरांत संबंधित रिटेल आउटलेट संचालक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निर्धारित उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध करा सकेंगे।

ग्राम पंचायतों के लिए 60 लाख 70 हजार रुपये एवं नगरीय निकायों के लिए 3 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन समस्या निवारण शिविर में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

आमजनों के हितों के लिए सरकार प्रतिबद्ध : अरुण साव

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव बीते शुक्रवार को जिला बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत आनंदगांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों एवं ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि जनता को अपने जायज कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, यह प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवेदनशीलता एवं सुशासन सरकार की कार्यशैली का प्रमुख आधार है तथा आमजनों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, बिजली तथा विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर आवेदन को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण किया जाए।

गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित है सरकार-शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। सरकार द्वारा जनता के हित में लगातार बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सरकार जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं का कर रही समाधान-बेमेतरा विधायक साहू ने कहा कि सरकार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी : कलेक्टर-कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही या ढीला-ढाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आम नागरिकों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से हल किया जाए।

हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया-उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिविर में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत नोनी सुरक्षा योजना के तहत 5 बालिकाओं को पंजीयन पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा 8 गर्भवती माताओं की गोदभराई तथा 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को सुपोषण किट वितरित की गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्ण होने पर 5 हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं।

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश-उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाई स्कूल उपकेंद्र परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दौर में पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है तथा यह आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से पौधारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

बीज पुंसवन अभियान का किया शुभारंभ-उप मुख्यमंत्री साव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए बीज पुंसवन अभियान का शुभारंभ किया। इस विशेष बीज पुंसवन को मिट्टी, गोबर एवं गोमूत्र के मिश्रण से तैयार किया गया है, जिसके भीतर बीज रखा गया है। बरसात के मौसम में इसे लगाने पर पौधा अंकुरित होगा। इस पहल से व्यापक स्तर पर पौधारोपण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, एसएसपी रामकृष्ण साहू, छत्तीसगढ़ विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, राजेन्द्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रात के अंधेरे में जारी डीजल का खेल, किसानों को कम और उद्योगपतियों को मनमाना सप्लाई के आरोप..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया और बरमकेला क्षेत्र में डीजल संकट के बीच अब कालाबाजारी और मनमाने वितरण के आरोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में किसान जहां घंटों लाइन में खड़े होकर डीजल के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पेट्रोल पंपों में रात के अंधेरे में उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों को भारी मात्रा में डीजल दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कई पेट्रोल पंप संचालक नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं।दरअसल, वैश्विक संकट और डीजल की कमी को देखते हुए जिला कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने हाल ही में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा और हर वाहन के लिए निर्धारित मात्रा तय रहेगी, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके और किसानों को पर्याप्त डीजल उपलब्ध हो सके। लेकिन जमीनी हालात प्रशासनिक दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं।

खेत छोड़ लाइन में लग रहे किसान-इन दिनों क्षेत्र में धान कटाई और खेतों की जुताई का काम तेजी से चल रहा है। किसान ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लेकर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें तय मात्रा में डीजल नहीं मिल पा रहा। कुछ जगहों पर सीमित मात्रा देकर वापस लौटा दिया जा रहा है, जबकि देर रात बड़े वाहनों और उद्योगों से जुड़े लोगों को आसानी से डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

प्रति लीटर 10 से 20 रुपये अतिरिक्त वसूली की चर्चा-सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि डीजल संकट के बीच कुछ जगहों पर प्रति लीटर 10 से 20 रुपये अतिरिक्त लेकर डीजल देने का खेल भी जारी है। आरोप है कि रात के समय मनमाने दाम पर डीजल सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में इस तरह की चर्चाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आ सकती है।

जांच टीम बनने के बाद भी जारी है खेल-डीजल वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दो दिन पहले तहसील स्तर पर जांच टीम गठित की थी। इसमें तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक को शामिल कर पेट्रोल पंपों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा था कि कालाबाजारी या नियम उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद क्षेत्र में रात के अंधेरे में डीजल वितरण और कथित अतिरिक्त वसूली का खेल जारी रहने की चर्चा प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रही है।

कार्रवाई का इंतजार, किसानों में बढ़ रही नाराजगी-अब किसानों और आम लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो खेती-किसानी का काम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि पेट्रोल पंपों की अचानक जांच कर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ताकि डीजल की कालाबाजारी और अवैध वसूली पर रोक लग सके तथा जरूरतमंद किसानों को राहत मिल सके।

मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सुविधा पर सवाल, बुजुर्ग मरीज को निजी अस्पताल का सहारा

ऑपरेटर नहीं होने का हवाला देकर लौटाने का आरोप

रायगढ/मूक पत्रिका

जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपये खर्च कर संचालित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान में मरीजों को बुनियादी उपचार सुविधाएं तक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि गंभीर मरीजों को भी डायलिसिस जैसी आवश्यक सुविधा के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब नंदेली निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग को डायलिसिस के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत गंभीर होने के कारण जिला चिकित्सालय से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजन उम्मीद लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए मरीज को अन्यत्र इलाज कराने की सलाह दे दी गई।सूत्रों की मानें तो मेडिकल कॉलेज में किडनी रोग विशेषज्ञ की कमी लंबे समय से बनी हुई है। यही वजह है कि कई बार डायलिसिस से जुड़े मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पाता। जबकि मेडिकल कॉलेज जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों मरीजों के लिए सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र माना जाता है। इसके बावजूद आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन रही है।परिजनों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में भटकने के बाद मजबूरी में बुजुर्ग मरीज को निजी चिकित्सा संस्थान ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर रूपेंद्र पटेल के संस्थान में डायलिसिस कराया गया।

निजी संस्था महंगे उपचार-हर वर्ग निजी चिकित्सा संस्थानों उपचार कराने समर्थ नहीं हो पाता है।ऐसे में इस शासकीय चिकित्सा सुविधाएं ही इनका सहारा होती है।परन्तु जब इन सरकारी अस्पतालों में ही मरीज को उपचार न मिले तो क्या महंगा उपचार कराने वह सक्षम होगा।स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर तब हो जाती है, जब डायलिसिस, गंभीर ऑपरेशन, जैसी सुविधाएं लेकर उन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से बैरंग लौटना पड़ता हैं। ऐसे मामलों में मरीज और उनके परिजन खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि शासन द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं अक्सर कमजोर नजर आती हैं।

बीज निगम में तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरोध में उग्र हुआ आंदोलन, SATHI पोर्टल व्यवस्था पर गहराया संकट

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का आंदोलन अब व्यापक रूप लेता जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान प्रबंध संचालक (स्ष्ठ) के तानाशाहीपूर्ण रवैये, कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा तथा श्रमिक हितों की अनदेखी के कारण निगम का वातावरण पूरी तरह भय और असंतोष से भर गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से बीज निगम और किसानों के हित में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आज अपने अधिकार, सम्मान और परिवार की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बजाय दबाव और प्रताड़ना की नीति अपनाई जा रही है। कर्मचारियों की जायज मांगों पर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि निगम में ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां अपनी बात रखने वाले कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके भविष्य को लेकर भय का वातावरण तैयार किया जाता है।कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निगम द्वारा स्वयं जारी आदेश क्रमांक 14005 दिनांक 15/03/2024 में श्रम विभाग के निर्देशानुसार दैनिक एवं मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ?4,000/- प्रतिमाह ÷श्रम सम्मान राशि÷ दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। आदेश में यह भी उल्लेखित है कि यह राशि 01 अगस्त 2023 से प्रभावशील होगी। इसके बावजूद वर्तमान प्रबंधन द्वारा दिसंबर माह से यह राशि बंद कर दी गई, जो कर्मचारियों के साथ खुला अन्याय है।कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन और निगम दोनों द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, तब कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि श्रमिक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान एमडी द्वारा कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर निगम में तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में कर्मचारियों की दो सूत्रीय प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं –

1. दिसंबर माह से बंद की गई ?4,000/- श्रम सम्मान निधि राशि को पुनः निरंतर जारी किया जाए तथा 1 अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक कार्यरत 65 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लंबित एरियर्स राशि तत्काल प्रदान की जाए।

2. आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के परिवार को ?50,000/- सहायता राशि प्रदान करने संबंधी सकारात्मक निर्णय लिया जाए, जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार की सुरक्षा और सम्मान का विश्वास मिल सके।हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि बीज निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्षों से कम वेतन और असुरक्षा की स्थिति में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद निगम और किसानों के हित में उन्होंने हमेशा जिम्मेदारीपूर्वक कार्य किया। लेकिन वर्तमान प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के श्रम और समर्पण का सम्मान करने के बजाय लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना SATHI पोर्टल पर पड़ रहा है। यह पोर्टल किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने, नकली बीजों पर रोक लगाने तथा बीज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। स्ड्डह्लद्ध पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादन, बीज परीक्षण, त्तक्र कोड आधारित ट्रैकिंग, ऑनलाइन स्टॉक प्रबंधन, निरीक्षण रिपोर्ट, बीज वितरण और किसानों तक जानकारी पहुंचाने जैसी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित होती है।

बस्तर संभाग में पहली बार आयोजित हुआ भव्य 'माँ तेली सत्ती महोत्सव', उमड़ा जनसैलाब

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर बस्तर संभाग के इतिहास में पहली बार माँ तेली सत्ती महोत्सव का भव्य आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक महोत्सव के अवसर पर कांकेर साहू समाज के सक्रिय सदस्यों द्वारा बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर में अनुकरणीय पहल की गई। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए समाज द्वारा सर्व समाज के नागरिकों, राहगीरों एवं यात्रियों के लिए ठंडे पानी और शरबत की विशेष व्यवस्था की गई थी। राहगीरों को राहत पहुंचाने वाली साहू समाज की इस निःस्वार्थ सेवा भावना और सामाजिक सरोकार की उपस्थित लोगों एवं नगरवासियों ने मुक्तकंठ से सराहना की। इस गरिमामयी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग एवं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे इन वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने माँ तेली सत्ती माता की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। साथ ही समाज द्वारा किए जा रहे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक सामाजिक कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में शिल्पा साहू ने कहा कि माँ तेली सत्ती केवल साहू समाज की आराध्य देवी नहीं हैं, बल्कि सुप्रसिद्ध केशकाल घाट से गुजरने वाले देश-प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि माता सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती आई हैं। हालांकि यह पहला तेली सत्ती महोत्सव है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका स्वरूप और अधिक भव्य, व्यापक तथा संगठित होगा, जो पूरे बस्तर संभाग में एक नई और विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। इस अवसर पर साहू समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें नगर अध्यक्ष कामेश्वर साहू, नगर उपाध्यक्ष खेमू साहू, एसआई सर दयालु राम साहू, संगठन सचिव संयोग साहू, नगर उपाध्यक्ष (महिला) हेमलता साहू, बृजलाल साहू, गोलीं साहू, हिम साहू, युक्ति साहू और प्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु एवं मातृशक्ति शामिल थीं। महोत्सव के दौरान पूरे समाज में एक विशेष उत्साह, सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने समाज में समरसता और सेवा भावना का एक बड़ा संदेश दिया।

कलेक्टर पदमिनी भोई साहू ने शासकीय कार्य में लापरवाही करने वाले पर की कार्यवाही

ग्राम पंचायत परसापाली का सचिव सस्पेंड

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर पदमिनी भोई साहू बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसापाली के धरती आबा शिविर में शामिल हुई। इस दौरान परसापाली के सरपंच एवं पंचों के द्वारा सुदर्शन हिरवानी ग्राम पंचायत सचिव परसापाली के विरुद्ध ग्राम पंचायत में नियमित उपस्थित नहीं होने, आम नागरिकों के आवेदन पत्र लेने हेतु ग्राम पंचायत में नही आने, जन्म-मृत्यु पंजीयन नही करने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में गंभीर शिकायत प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा त्वरित रूप से शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सुदर्शन हिरवानी ग्राम पंचायत सचिव परसापाली को निलंबित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिया गया। जिस पर इन्द्रजीत बर्मन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ द्वारा सुदर्शन हिरवानी को उनके सरकारी कार्य में लापरवाही के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बिलाईगढ़ निर्धारित किया है।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, दूध नदी और तालाबों की स्वच्छता पर दिया जोर

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर वन विभाग के सौजन्य से कांकेर शहर एवं जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सहयोग समाजसेवी संस्था के अध्यक्ष एवं समाजसेवी अजय ÷पप्पू÷ मोटवानी ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कांकेर की जीवन रेखा मानी जाने वाली दूध नदी तथा ऐतिहासिक तालाबों का संरक्षण बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि उनकी संस्था वर्षों से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। संस्था किसी आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि आम जनता से सक्रिय सहभागिता चाहती है ताकि नदी और तालाबों में घरों तथा दुकानों का कचरा न डाला जाए। उन्होंने कहा कि लगातार सफाई के बावजूद यदि लोग दोबारा कचरा फेंकते हैं तो स्वच्छता अभियान की सफलता प्रभावित होती है। अजय मोटवानी ने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना कचरा नगर पालिका के वाहनों को दें तथा नदी-तालाबों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन-प्रशासन का नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉ. शैलेंद्र सिंह, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर, पंडित सीताराम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार कांकेर, प्रवीण गुप्ता, समाजसेवी कांकेर, टी.के. जैन, भूतपूर्व सैनिक कांकेर तथा मनोज दुबे समाजसेवी उपस्थित रहे। इसके अलावा वन विभाग की ओर से उपवन मंडल अधिकारी कांकेर, वन परिक्षेत्र अधिकारी कांकेर, वन परिक्षेत्र अधिकारी सरोना, वन परिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरर, वन परिक्षेत्र अधिकारी चारामा सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरहरदेव के शिक्षक अमित कुमार सिंह, सौरभ साहू तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी शामिल हुए।

बालपुर में उमड़ा जनस्नेह, चन्द्रदेव राय के जन्मोत्सव व वैवाहिक वर्षगांठ समारोह में जुटे हजारों लोग

बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बालपुर स्थित गृह निवास में पूर्व संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व विधायक बिलाईगढ़ चन्द्रदेव राय का जन्मोत्सव एवं वैवाहिक वर्षगांठ समारोह हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्यता, आत्मीयता और जनसमर्थन के अभूतपूर्व माहौल के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेशभर से संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार एवं हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी व ग्रामीणजन शामिल हुए। सुबह से ही बालपुर में शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। गृह निवास पहुंचने वाले लोगों ने पुष्पगुच्छ, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर विधायक चन्द्रदेव राय को जन्मदिन एवं शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दीं। पूरे आयोजन स्थल पर उत्साह, अपनापन और जनआस्था का वातावरण देखने को मिला। समारोह में विशेष रूप से महंत राम सुंदर दास का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहीं इन्द्र साव भाटापारा विधायक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन, पूर्व विधायक प्रतिनिधि घनश्याम मनहर, कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष शुभम बाजपेयी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। सूरज तिवारी, छत्रसाल साहू, हेमंत दुबे, सुरेंद्र भार्गव, पुरुषोत्तम साहू, तोषराम साहू, प्रदीप यादव, सहदेव सिदार, पवन अग्रवाल, सुनील सिंघानिया, दीपक अग्रवाल, पंकज चंद्रा, बलराम देवांगन, संजय दुबे, गोपाल पांडेय, भवानी श्रीवास, रामेश्वर खटकर, परमानंद साहू, नंद किशोर गोयल, मुँद्रिका राय, भागीरथी चंद्रा, प्रमोद साहू, गणेश यादव, विष्णु चंद्रा, इस्माइल खान, युवराज निराला, हेमंत बंजारे, उमेश कुर्रे, सिद्धांत मिश्रा, पल्लवी हेमंत दुबे, गीता पटेल, केशव साहू, राकेश पटेल, खेमराज चंद्रा, हरिहर साहू, विक्रांत साहू, कुमार देवांगन सहित बड़ी संख्या में लोग समारोह में मौजूद रहे। समारोह केवल जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जनसंपर्क, सामाजिक सौहार्द और जनविश्वास का विशाल मंच बनकर उभरा। बालपुर से लेकर बिलाईगढ़ तक पूरे क्षेत्र में आयोजन की चर्चा रही। भारी गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और देर रात तक शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी रहा।

जनसमस्या निवारण शिविर बना सुशासन का सशक्त माध्यम

विधायक दीपेश साहू बोले—सरकार गांव-गरीब के द्वार तक पहुंचाकर दे रही योजनाओं का लाभ

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत चोरभट्टी के स्कूल परिसर में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में क्लस्टर की 18 ग्राम पंचायतों से हजारों ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं, मांगों एवं योजनाओं के आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू उपस्थित रहे। विधायक ने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता और समयसीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

÷सुशासन, संवेदनशीलता और सेवा÷ के मंत्र पर कार्य कर रही सरकार-अपने संबोधन में विधायक दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ÷सुशासन, संवेदनशीलता और सेवा÷ के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज शासन स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और उनका समाधान कर रहा है, यही सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर जनता और शासन के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधायक ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि आम नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।

ग्रामीणों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं-शिविर के दौरान सरपंचों एवं ग्रामीणों की मांग पर विधायक दीपेश साहू ने ग्राम चोरभट्टी में प्राथमिक शाला अहाता निर्माण एवं उचित मूल्य राशन दुकान, ग्राम बुरनबोड़ में सामुदायिक भवन तथा ग्राम पिपरभट्ठा में उचित मूल्य दुकान भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बेमेतरा में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को निशुल्क लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया जा रहा है।

युवाओं, किसानों और आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस-विधायक साहू ने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए श्रीराम एकेडमी के माध्यम से निशुल्क कोचिंग सुविधा दी जा रही है तथा शीघ्र ही श्रीराम लाइब्रेरी की भी शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापना की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए विधायक ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत बजट में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अमोरा बैराज को स्वीकृति मिली है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा दुर्ग-बेमेतरा मार्ग, बेमेतरा-बेरला-अहिवारा मार्ग तथा कवर्धा से सिमगा तक सड़क निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है।

पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का दिया संदेश-शिविर में विधायक दीपेश साहू ने ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधरोपण करने एवं पौधों के संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढा निर्माण को बढ़ावा देने की अपील भी की 7 कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपेश साहू ने लगभग 18 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें ग्राम चोरभट्टी में शिवदयाल साहू के घर से मुखिरमुखी राम साहू के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य, ग्राम गुनाबोर में गली सीमेंट्रीकरण कार्य तथा ग्राम चोरभट्टी में हाईमास्ट लाइट स्थापना कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही ग्राम चोरभट्टी एवं गुनाबोर में पूर्ण हुए अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।

विभागीय स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की दी गई जानकारी-शिविर में स्कूल शिक्षा, पुलिस, लोक निर्माण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, खाद्य, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, उद्यानिकी, खेल, प्रधानमंत्री आवास योजना, मत्स्य, सहकारिता, श्रम विभाग एवं लोक सेवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं सामग्री वितरित की गई। राजस्व विभाग द्वारा किसानों को किसान किताब प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग ने हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए तथा निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत पोषण सामग्री का वितरण किया। इसके अलावा नोनी सुरक्षा योजना के तहत एलआईसी बीमा बॉन्ड प्रमाण पत्र एवं सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत पासबुक प्रदान की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि एवं सम्मान प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में 15 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की चाबी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र तथा पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गजानन साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष छोटूराम साहू, महामंत्री डेरहा देवांगन, भागीरथी साहू, लव साहू, सचिन ठाकुर, सदीप यादव, जनपद सदस्य जितेंद्र यादव, सरपंच रेखा पात्रे, उपसरपंच सनत साहू, सचिव राजकुमार साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

संपादकीय

पेपर लीक मामलों में उच्च स्तर पर जवाबदेही तय करने की जरूरत

अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लाखों विद्यार्थी एक भरोसे के साथ जिस परीक्षा में अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बैठें, वह सिर्फ उनके हित में साबित हो, जिनकी पहुंच उसके प्रश्नपत्र तक हो।देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी को सबसे अच्छे प्रबंधन के तहत संचालित करने का दावा किया जाता रहा है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इसमें जिस स्तर की गड़बड़ियां सामने आई हैं, उसमें यह सवाल उठा है कि हर बार कार्रवाई के तौर पर कुछ औपचारिक और दिखावे के कदम उठा कर क्या परीक्षा के प्रश्नपत्र बाहर आने की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है?यह इस वर्ष फिर साबित हुआ है कि पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया और ऐसे जरूरी कदम नहीं उठाए गए, जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित हो। नतीजतन, इस महीने के शुरू में आयोजित नीट के प्रश्नपत्र लीक होने की खबर आई। फिर मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा को रद्द कर देना ही सबसे आखिरी उपाय माना गया, जिसकी वजह से करीब बाईस लाख विद्यार्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया।सवाल है कि इस अफसोसनाक स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए सबसे बेहतर व्यवस्था के तहत परीक्षाओं के आयोजन का भरोसा देती रही है, क्या नीट-यूजी में प्रश्नपत्र लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों की निरंतरता कायम रहने की स्थिति में अब भी वह अपनी साख और प्रतिष्ठा के बने रहने का दावा कर सकती है?प्रश्नपत्र लीक होने के तथ्य सामने आने, उसके राजस्थान के कई कोचिंग संस्थानों में पहुंचने और मोटी रकम लेकर विद्यार्थियों को बेचने की खबरों के बाद सरकार ने मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी। उसके बाद से अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एनटीए की एक विशेषज्ञ भी शामिल हैं।अगर खुद एनटीए की ओर से इतनी अहम जिम्मेदारी संभालने वाला कोई शख्स ही प्रश्नपत्र लीक करने का आरोपी हो, तो ऐसे में किसी संस्था की साख की क्या अहमियत रह जाती है?गौरतलब है कि इस तरह की गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एनटीए में ढांचागत सुधार की सिफारिश की थी। इसके अलावा, संसद में परीक्षाओं के संदर्भ में संगठित तौर पर पेपर लीक जैसी किसी गड़बड़ी के लिए दस वर्ष की कैद के प्रावधान वाला कानून पारित किया गया। साथ ही अन्य सभी कमियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों सहित आधुनिक तकनीक से लैस बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई।इस सबके बावजूद अगर नीट-यूजी का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है और यहां तक कि परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है, तो यह किसकी नाकामी है? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या इस व्यापक गड़बड़ी का दायरा वैसे ही निचले स्तर के आरोपियों तक सिमटा हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट परीक्षा के आयोजन में यह कोई पहला मामला सामने आया है।

फिर कैसे मिले सुर मेरा-तुम्हारा

राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय।

(उमेश चतुर्वेदी)

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं।

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ धांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी हैं।

दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लॉक की एकता से बेपरवाह रहीं ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तृणमूल की ताबूत का कील ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिरे से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक-दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकम्मल एकता की उम्मीद बचती है? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लॉक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है।

गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता लेकिन कांग्रेसी आलाकमान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी-नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लॉक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखा भी। विपक्ष को उसी वक्त चेतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असर यह हुआ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। बाकी कसर बीते विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी है।

गौर करने की बात है कि जब भी सत्ता पक्ष के उफान में विपक्ष बह जाता है, उसकी एकता की छटपटाहट बढ़ जाती है। ज्यादातर यह अस्तित्व संकट टालने का यह फौरी उपाय होता है। तब वह हार के बाद वोटों के गुणा-गणित में जुट जाता है। फिर उसे इलहाम होता है कि अगर वह एक रहता तो वह भारी पड़ता। 1962 के आम चुनावों में नेहरू को फूलपुर की सीट पर सीधी चुनौती में हार मिलने के बाद लोहिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। तब भारी उत्सुकता और उत्साह के बावजूद लोहिया हार गए थे। इसके बाद उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार दिया। तब कांग्रेस को 44 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लोहिया को लगा कि विरोध में पड़े 56 प्रतिशत वोटों को अगर एक किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। गैर कांग्रेसवाद के बैनर के तले उन्होंने 1963 के उपचुनावों और 1967 के आम चुनावों में इसे आजमाया। इसका असर यह हुआ कि आठ राज्यों से कांग्रेस की विदाई हो गई। तब से सत्ता में आने वाली पार्टी के खिलाफ बाकी विपक्ष की एकता के सुर उठने की परंपरा बन गई है। कभी यह कांग्रेस के खिलाफ होता था, जिसमें वाममोर्चा और जनसंघ- बीजेपी भी शामिल रहते थे, अब यह भाजपा के खिलाफ हो रहा है।

प. बगाल के बीते विधानसभा चुनाव में ममता को जहां करीब 42 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं बीजेपी को करीब 46 प्रतिशत। कांग्रेस को 2.97 और वाममोर्चे को 4.45 प्रतिशत वोट मिले हैं। गैर बीजेपी वोटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 49 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। चुनावी राजनीति में सात प्रतिशत का अंतर बड़ा होता है। अब विपक्षी खेमे को लग रहा है कि अगर वे एक होते तो बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलती। वैसे चुनावी गणित सामान्य गणित की तरह नहीं होता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी को पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में वह पिछड़ गई थी। चुनावी मैदान में जब सिर्फ दो खेमे होते हैं, तब मतदाताओं के बीच लंबवत ध्रुवीकरण हो जाता है। तब बिखराव वाले आंकड़े भी बदल जाते हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ दिखा, जब बीजेपी सब पर भारी रही।

संसदीय चुनाव में सफलता के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की 99 सीटों के बाद 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी विपक्ष का दूसरा बड़ा दल है। तीसरे नंबर पर 29 सीटों के साथ ममता ही हैं। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक के पीछे ममता का भी विचार था, फिर भी ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस या ब्लॉक के दूसरे दलों को तवज्जो दिया। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की खींचतान जारी रही। विपक्ष के किसी भी दल ने एकता की कीमत पर त्याग स्वीकार नहीं किया। विपक्षी खेमे का संकट यह है कि वह अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सहयोगियों से हिस्सेदारी बांटना ही नहीं चाहता।

मजबूत एकता के लिए विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य साफ छवि वाला चेहरा होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा चेहरा है भी नहीं। ममता बड़ी नेता तो हैं, लेकिन उनकी तुनकमिजाजी उन्हें सर्वमान्य चेहरा मानने के राह की बड़ी बाधा है। राहुल मोदी-शाह की जोड़ी को चाहे जिस अंदाज में चुनौती दें, मोदी विरोधी बौद्धिकों को उनका यह अंदाज चाहे जितना भी पसंद हो, लेकिन आमजन को उनमें कई बार बचकानापन नजर आता है तो कई मर्तबा प्रहसन। स्टालिन चाहे जितनी अच्छी तमिल बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर स्वीकार्यता के लिए वे अयोग्य हैं। इसी तरह केजरीवाल के पास बड़ा आधार नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की तो, वे भी जमीनी राजनीति के बजाय बयानों के गुब्बारे उड़ाने के उस्ताद होते गए हैं।

आपसी अहं के टकराव के चलते नीतीश विपक्षी खेमा छोड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी नेता ममता को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त मिल गई है। अखिलेश को भी अगले साल उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी से दो-दो हाथ करना है। बीजेपी की कोशिश उन्हें तीसरी बार शिकस्त देने की होगी। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रही तो उसके सामने दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे का संकट बड़ा है। अतीत के विपक्षी व्यवहार से नहीं लगता कि शायद ही भविष्य में कोई मजबूत मोर्चा बन सके। खुलकर विपक्षी खेमा भले ही ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जरूर गुनगुना रहा है, कैसे मिले सुर हमारा-तुम्हारा....लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आवारा कुत्तों की भयावह समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- लेकिन जिम्मेदारी तय किए बिना कैसे बनेगी बात?

(संतोष कुमार पाठक)

लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों - खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और दूसरी जगह भेजने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत देश भर में कुत्ता काटने की घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में अपने पहले के आदेश की फिर से याद दिलाते हुए कहा कि सड़क के कुत्तों पर 7 नवंबर, 2025 को दिया गया उनका आदेश ही लागू होगा। इन आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए और जो अधिकारी इनका पालन न करे, उन पर विभागीय और अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

लेकिन क्या इससे देश के आम नागरिकों को खुश होना चाहिए? क्या इससे देश में आवारा कुत्तों से परेशान लोगों - खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल पाएगी? यह इतना भी आसान नहीं है। जब तक किसी खास अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि ज्यादातर राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लेती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए इस आदेश को लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी यानी सीधे ठ्ठरूको ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए गए आदेश के 6 महीने बीत जाने के बावजूद हालत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली का नगर निगम - एमसीडी कुत्तों को रखने के लिए एक डॉग सेंटर तक तैयार नहीं कर पाई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो कुत्ता एक से अधिक बार लोगों को काट चुका हो, उसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत राज्य के कई जिलों में भी अभी भी जरूरी डॉग सेंटर का निर्माण फाइल्स में ही अटका पड़ा है। क्या इस तरह की लापरवाही और लेट-लतीफी के लिए जिलों के डीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए?

समय आ गया है कि हर जिले, हर राज्य और सबसे ऊपर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर कॉल करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत उनकी शिकायत का एक नंबर भी अलॉट कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो टोल फ्री नंबर पर बैठने वाले अदालत के स्टॉफ का खर्चा भी लोगों से ले सकता है और इसके लिए प्रति कॉल 3 से 5 रुपए की राशि भी फिक्स की जा सकती है लेकिन हर कॉल का उचित फॉलोअप सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस काम को युद्धस्तर पर करने की जरूरत है क्योंकि भारत में आवारा कुत्तों के काटने की समस्या दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। वैसे तो देश में कुत्तों द्वारा काटने के सारे आंकड़े दर्ज नहीं करवाए जाते हैं लेकिन जो भी आंकड़े दर्ज होते हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2024 में हर मिनट पर डॉग बाइट के 7, हर घंटे में 430, रोजाना 10,321 , हर महीने 3,09,643 और वर्ष भर में 37,15,713 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी सरकार भी यह मान रही है कि एक साल में 37 लाख से भी ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। वहीं वर्ष 2025 में कुत्तों के काटने की संख्या 47 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है।

सरकारी रिपोर्ट की माने तो, भारत में हर साल रेबीज के कारण 300 लोगों की मौत होती है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 18 से 20 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। यहां इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस तरह के ज्यादातर मामले आंकड़ों में दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2019 में हुई पशु जनगणना में, देश में आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ बताई गई थी। लेकिन एक मोटे अनुमान के तौर पर यह माना जाता है कि देश में वर्तमान में आवारा कुत्तों की संख्या 6 से 7 करोड़ के लगभग हो गई है।

यह समस्या हर गुजरते दिन के साथ भयावह होती जा रही है। मोहल्लों, कॉलोनियों, सोसायटियों यहां तक कि पार्कों में भी इन आवारा कुत्तों ने कब्जा जमा रखा है। लगभग हर मोहल्ले/कॉलोनी और सोसायटी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन्हें अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिलाएंगे, बल्कि उनकी जिद होगी कि वो इन्हें बाहर ही खाना खिलाएंगे। रही-सही कसर देश के टीवी चैनलों पर आने वाले तथाकथित ज्योतिषियों ने पूरी कर दी है, जो खास रंग के कुत्तों को खाना खिलाने पर किस्मत बदल जाने यानी अच्छे दिन आने का सपना दिखाकर इस समस्या को और ज्यादा भयावह बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पीएम की यात्रा से पूरी दुनिया में मची हलचल, भारत की ताकत देखकर दंग रह गए यूरोपीय देश

(नीरज कुमार दुबे)

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी अब स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, हरित नौवहन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नॉर्वे यात्रा ने भारत और नॉर्वे के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ओस्लो में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, निवेश और व्यापार के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग का आधार भी माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस नई साझेदारी से जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री अर्थव्यवस्था और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में सहयोग को रणनीतिक दिशा मिलेगी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को उन ताकतों के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा जो कूटनीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी का हथियार की तरह उपयोग करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी अब स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, हरित नौवहन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि चार दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया है। ऐसे समय में जब भारत पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता कम कर नए आर्थिक सहयोगियों की तलाश कर रहा है, नॉर्वे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। नॉर्वे का सरकारी पेंशन कोष दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु

निवेश कोषों में गिना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में उसने भारतीय बाजारों में निवेश लगातार बढ़ाया है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में नॉर्वे का हिस्सा 1.95 प्रतिशत था, जो 2025 तक बढ़कर 3.87 प्रतिशत हो गया। महामारी के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी तेजी आई है। भारत को हाल के वर्षों में नॉर्वे से लगभग 693 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। व्यापार के स्तर पर भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का नॉर्वे को निर्यात बढ़कर लगभग 472 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात लगभग 635 मिलियन डॉलर रहा।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को नया आयाम देना भी शामिल है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने नॉर्वे में पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन नियंत्रण, जैव आधारित प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। मोदी को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री को मिला 32वां विदेशी सम्मान है।

इसके अलावा, भारत और नॉर्वे के अनुसंधान संस्थानों के बीच संयुक्त कार्यशालाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और वैज्ञानिक आदान प्रदान की भी योजना बनाई गई है। विशेष रूप से समुद्री ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा पर सहयोग भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करेगा और कार्बन तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री विज्ञान, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है।

प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बैठकें भी इस दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहीं। उन्होंने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रन फ्रॉस्टडॉटिर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ अलग अलग वार्ता की। इन बैठकों में व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

हम आपको बता दें कि नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। इन पांच देशों की संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद क्षमता 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत समुद्री शासन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व रखते हैं। साथ ही ओस्लो में आयोजित तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत और इन देशों के बीच प्रौद्योगिकी, हरित परिवर्तन, रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था और आर्कटिक सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा तेज हुई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच निवेश समझौते को सहयोग की अधूरी कड़ी बताया। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हाल में हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से भारत में एक लाख करोड़ डॉलर तक का निवेश आ सकता है और अगले पंद्रह वर्षों में दस लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं।

हम आपको बता दें कि फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के साथ भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। फिनलैंड की सौ से अधिक कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, जबकि डेनमार्क की कई कंपनियों ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत नए कारखाने स्थापित किए हैं। आइसलैंड में भारतीय संस्कृति, योग, संगीत और भारतीय भोजन के प्रति विशेष रुचि देखी जा रही है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे और नॉर्डिक देशों की यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हरित विकास, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं का संकेत मानी जा रही है। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ती निकटता आने वाले वर्षों में वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के नए मॉडल के रूप में उभर सकती है।

ओपीडी में मेडिसिन विशेषज्ञ नदारद, डॉ. लोकेंद्र कश्यप को हटाने के बाद और बिगड़े हालात

घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज लौट रहे मरीज,भीषण गर्मी में बुजुर्ग और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित

जिला अस्पताल का हाल बेहाल

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

जिला अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी अब मरीजों पर सीधे असर डाल रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी क्रमांक 20, जहां मेडिसिन विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती थीं, वहां फिलहाल कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसके चलते प्रतिदिन इलाज की आस लेकर पहुंचने वाले मरीजों को बिना उपचार के ही लौटना पड़ रहा है। यह स्थिति डॉ. लोकेंद्र कश्यप की संविदा सेवा समाप्त किए जाने के बाद और अधिक गंभीर हो गई है। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीज घंटों लाइन में लगने के बाद जब यह जान पाते हैं कि

मेडिसिन विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। भीषण गर्मी के बीच बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक बन गई है। कई मरीजों ने बताया कि वे सुबह से अस्पताल परिसर में बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर न मिलने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिले में पहले से ही एमडी मेडिसिन डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। जिला अस्पताल, सीएचसी, बीडीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मिलाकर जिले में कुल 12 मेडिसिन विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति बेहद चिंताजनक है। हाल ही में जिला अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. लोकेंद्र कश्यप की संविदा सेवा एकतरफा नोटिस के जरिए समाप्त कर दी गई, जिसके बाद मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। डॉ. लोकेंद्र कश्यप की सेवा समाप्ति को लेकर छत्तीसगढ़ इनसर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (सीडा) पहले ही विरोध जता चुका है। संगठन का कहना है कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर को हटाने का सीधा असर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है, जिसका खामियाजा अब आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिसिन विभाग से जुड़े बुखार, सांस की बीमारी, शुगर, बीपी, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या सबसे अधिक रहती है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर न होने से समय पर इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। मरीजों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें दूसरे जिलों के अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे समय, पैसा और जोखिम तीनों बढ़ रहे हैं। सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि डॉ. लोकेंद्र कश्यप के सेवा समाप्ति आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और साथ ही जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में शीघ्र मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में जांजगीर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर और अधिक दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा।

भूपदेवपुर, पुसौर व लैलूंगा थाना क्षेत्र में शराब रेड, 3 आरोपी गिरफ्तार, 31 लीटर अवैध शराब जब्त

रायगढ़/मूक पत्रिका

एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर चलाए जा रहे ÷ऑपरेशन आघात÷ के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना भूपदेवपुर, पुसौर एवं लैलूंगा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर रेड कार्रवाई करते हुए कुल 31.155 लीटर अवैध शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना भूपदेवपुर क्षेत्र में ग्राम चारभांठा के पास एनएच-49 स्थित पान ठेले में अवैध शराब बिक्री की सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग एवं आबकारी उप निरीक्षक अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई। जांच में पता चला कि ग्राम चारभांठा निवासी दमोदर चौहान एवं उसका करीबी घर तथा हाईवे किनारे स्थित पान ठेले में अवैध शराब बिक्री करते हैं। रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी दमोदर चौहान के घर पर रेड

कार्रवाई में उसके कब्जे से 15.155 लीटर देशी एवं विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें हंटर बीयर, मेडुसा बीयर, गोवा स्पेशल व्हिस्की तथा यूनिक देशी मदिरा शामिल है। जब्त शराब की कुल कीमत 5840 रुपये है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपी दामोदर चौहान पिता बैसाखु चौहान 62 साल निवासी चारभांठा, थाना भूपदेवपुर व 01 अन्य के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी दामोदर चौहान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी फरार है जिसकी तलाश जारी है।

थाना पुसौर की रेड कार्रवाई, तडोला चौक में हाथ भट्ठी महुआ शराब बेचते आरोपी दबोचा-इसी प्रकार पुसौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम तडोला चौक के पास एक व्यक्ति हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल रेड कार्रवाई कर आरोपी नरेश भाष्कर पिता सीताराम भाष्कर उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम तडोला थाना पुसौर को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 6 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 1200 रुपये बरामद की गई। आरोपी द्वारा शराब बिक्री हेतु रखना स्वीकार करने पर उसके विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

लैलूंगा में जंगल मार्ग से महुआ शराब लेकर जा रहा आरोपी पकड़ाया-वहीं थाना लैलूंगा क्षेत्र में थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम माड़ो जंगल पगडंडी मार्ग में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति सफेद झोला लेकर आते मिला, जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शनिराम पैंकरा पिता स्वर्गीय पैयराम पैंकरा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम माड़ो ग्राम पंचायत लोहड़ापानी थाना लैलूंगा बताया। आरोपी के कब्जे से दो जरीकेन में कुल 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद की गई जिसकी कीमत 1500 रुपये है।

'नन्हे सितारे समर कैंप' बना आदिवासी बच्चों के सपनों की उड़ान, जिला मुख्यालय के भ्रमण से बच्चों में जगा उत्साह

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /:-उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श हरेश मंडावी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ÷नन्हे सितारे फंड एंड लर्न समर कैंप-2026÷ बच्चों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन का अनूठा संगम बनकर उभर रहा है। समर कैंप के तीसरे दिन दूरस्थ आदिवासी अंचलों से आए बच्चों को जिला मुख्यालय के महत्वपूर्ण संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया, जिससे उनके भीतर नई जिज्ञासा और अपने सपनों को साकार करने की ललक दिखाई दी। कोयलीबेड़ा विकासखंड के

ग्राम बड़पारा और पानीडोबीर सहित अन्य सुदूर गांवों से पहुंचे बच्चों ने पहली बार जिला मुख्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ढांचों को इतनी नजदीक से देखा और समझा। इस विशेष भ्रमण के दौरान बच्चों ने कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, नरहरदेव उत्कृष्ट विद्यालय, मावा मोदोल कोचिंग सेंटर और वित्तीय साक्षरता केंद्र सहित अन्य प्रमुख संस्थानों का अवलोकन किया। वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बच्चों को इन संस्थानों की कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी बेहद सरल और रोचक तरीके से दी। भ्रमण के दौरान बच्चों के चेहरे पर गजब का उत्साह और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई दिया। कई बच्चों ने प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल मनोरंजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। इस समर कैंप में शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। समर कैंप के अंतर्गत प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें लोकनृत्य, समूह गीत, संगीत एवं रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक अभिव्यक्ति के इस सुंदर समन्वय ने पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और बेहतरीन मंच संचालन क्षमता ने सभी को गहराई से प्रभावित किया, जिससे पूरे परिसर में उत्साह, उमंग और आनंद का वातावरण निर्मित हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रमेश निषाद एवं डीएमसी नवनीत पटेल ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इस समर कैंप में 300 से अधिक बच्चे बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जिसमें अकेले पानीडोबीर क्षेत्र के ही 100 विद्यार्थी शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी पालकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को इस कैंप में शामिल कर उनका उत्साहवर्धन करें। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों के बच्चों को अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने, नए अनुभव प्राप्त करने तथा एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं।

श्रीराम मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष पद चुनाव की तैयारियां शुरू, नागेंद्र गुप्ता बने मुख्य निर्वाचन अधिकारी

चांपा/मूक पत्रिका

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों के हितों के लिए सक्रिय छत्तीसगढ़ राज्य से पंजीकृत संस्था श्री राम मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समिति में लगभग दो हजार पंजीकृत सदस्य हैं, जिनकी सहभागिता से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए 27 मई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान स्थल समिति का मुख्य कार्यालय केराझरिया निर्धारित किया गया है। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मतगणना कर विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए समिति ने पूर्व पार्षद नागेंद्र गुप्ता को सर्वसम्मति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं यासीन मेमन एवं किशन नामदेव को निर्वाचन पर्यवेक्षक, जबकि नरेंद्र वैष्णव एवं विमल राठौर को सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति के अध्यक्ष धजा राम साहू, संरक्षक समद बेग एवं बहरता राम धीवर ने सभी नवनियुक्त निर्वाचन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने की अपेक्षा व्यक्त की है।

खनिज पदार्थों के अवैध खनन परिवहन करते हाईवा और पोकलेन मशीन जप्त

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

खनिज पदार्थों के अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा तहसील सारंगढ़ एवं सरिया के ग्राम टिमरलगा एवं कटंगपाली क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला ने बुधवार को टिमरलगा में हाईवा क्रमांक छत्र-13-ए क्यू -4622 एवं गुरुवार को ग्राम कटंगपाली में खनिज डोलोमाईट का अवैध उत्खनन करते हुए पोकलेन 210 पर जप्ती की कार्यवाही की है। इन वाहनों को क्रमशः थाना सारंगढ़ एवं सरपंच प्रतिनिधि कटंगपाली (दयाराम मिरी) के सुपुर्दगी में दिया गया। इस कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई।

सहकारी समिति और खाद दुकानों का किया गया निरीक्षण, दिलीप ट्रेडर्स हरदी एवं साहू कृषि केन्द्र मल्दा अ को मिला नोटिस

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश और आशुतोष श्रीवास्तव उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में गुरुवार को जिले के कई सहकारी और निजी विक्रय केन्द्रों का जयप्रकाश गुप्ता, उर्वरक निरीक्षक, मायाशंकर जोल्हे एवं जुगेश्वर पटेल बीटीएम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सहकारी समितियों में खाद एवं बीज अनुशंसित मात्रा में वितरण करने निर्देशित किया गया। समिति में उपस्थित किसानों को

भी संतुलित खाद उपयोग करने तथा तत्काल खाद उठाव करने सलाह दिया गया। विकासखण्ड सारंगढ़ अंतर्गत मेसर्स सेवा सहकारी समिति कोसीर, साहू कृषि केन्द्र मल्दा अ, गीता ट्रेडर्स, चन्द्रा कृषि केन्द्र जशपुर, दिलीप ट्रेडर्स हरदी का निरीक्षण किया गया। निजी संस्थाओं द्वारा एफसीओ का उल्लंघन करते पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए मेसर्स दिलीप ट्रेडर्स हरदी एवं साहू कृषि केन्द्र मल्दा अ को नोटिस जारी किया गया।

23 मई को थाना परिसर कोसीर में होगा प्रायवेट सुरक्षा कर्मी की भर्ती

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के इच्छुक महिला और पुरुष बेरोजगारों को सुरक्षाकर्मी का रोजगार देने के लिए निजी सुरक्षा कंपनी एसआईएस लिमिटेड अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा 23 मई को थाना परिसर कोसीर में निशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8103841655 से सम्पर्क कर सकते हैं। जिले में आगामी शिविर- इस निजी सुरक्षा कंपनी का सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में शिविर सुबह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है, जिसके अनुसार 25 मई को थाना परिसर सरसीवा, 26 मई को थाना परिसर केडार, 28 मई को थाना परिसर डोंगरीपाली, 29 मई को थाना परिसर बेलादुला, 30 मई को थाना परिसर सलिहा और 31 मई को थाना परिसर सारंगढ़ में आयोजित किया जाएगा। देश और राज्य के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे शहरों के सरकारी और निजी अस्पताल, कंपनी ड्यूटी करने पर प्रतिमाह 10 से 20 हजार का वेतन सहित कुछ सुविधा कंपनी उपलब्ध कराएगी।

धाराशिव सुशासन शिविर में तत्काल 37 हितग्राहियों का बना राशन कार्ड, कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने किया स्टॉल निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धाराशिव में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के 17 गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जहां आमजनों की समस्याएं सुनी गईं और आवेदन प्राप्त किए गए।

शिविर में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति और आमजनों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। सुशासन शिविर में तत्काल 37 हितग्राहियों का

राशन कार्ड बना। शिविर में कुल 2198 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण तथा महतारी वंदन योजना से जुड़े आवेदन सबसे अधिक रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं के तहत सामग्री एवं लाभ भी वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 अन्नप्राशन एवं 3 गोदभराई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहकारिता विभाग द्वारा 2 किसानों को स्वर्णना धान बीज वितरित किया गया तथा एक किसान को बिना ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान किया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्राम धाराशिव की 5 महिला हितग्राहियों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। उद्यानिकी विभाग द्वारा 7 महिलाओं को फलदार पौधों का वितरण किया गया। वहीं संतोषी मछवारा समिति को मछली पकड़ने हेतु जाल प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं 2 हितग्राहियों को फूड बॉक्स वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड प्रदान किए गए। कृषि विभाग द्वारा 10 किसानों को जैविक कीटनाशक किट वितरित की गई। शिक्षा विभाग द्वारा 9 स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किया गया। साथ ही 6 बच्चों को जाति प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

सण्ड्रा में युवाओं संग क्रिकेट खेलकर कलेक्टर ने बढ़ाया उत्साह

जंगलों-पहाड़ों के बीच पहुंचा प्रशासन, जन चौपाल में सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार- जिले के सुदूर और संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की सक्रिय मौजूदगी शुक्रवार को उस समय देखने को मिली, जब कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव और जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने ग्राम पंचायत सागमेटा, सण्ड्रा, एडापल्ली और पीलूर पहुंचकर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों के गांव पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह और विश्वास का माहौल दिखाई दिया। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, राशन वितरण, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा, आवागमन तथा अन्य मूलभूत समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। कलेक्टर विश्वदीप ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।उन्होंने ÷बस्तर मुन्ने÷ कार्यक्रम के तहत शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए पात्र ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज सरलता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से हितग्राहियों तक पहुंचाने को कहा। दौरे के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे जनगणना कार्य की समीक्षा भी की। ग्रामीणों को जनगणना के महत्व और शासन की योजनाओं से उसके सीधे संबंध के बारे में जानकारी दी गई तथा सक्रिय सहयोग की अपील की गई। एसपी जितेन्द्र यादव ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक सहभागिता और आपसी सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और ग्रामीणों के बेहतर समन्वय से क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण मजबूत होगा।सीईओ नम्रता चौबे ने पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और गति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।ग्रामीणों ने जन चौपाल में खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे, जिन पर कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय बाद प्रशासनिक अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जिससे लोगों में विश्वास और उम्मीद बढ़ी है।

युवाओं संग क्रिकेट खेलकर कलेक्टर ने बढ़ाया उत्साह

ग्राम सण्ड्रा में दौरे के दौरान कलेक्टर श्री विश्वदीप युवाओं के साथ क्रिकेट मैदान में उतरे। उन्होंने युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा खेल, शिक्षा और सकारात्मक सोच के माध्यम से समाज एवं जिले के विकास में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि बीजापुर में सकारात्मक बदलाव और विकास यात्रा के सबसे बड़े भागीदार युवा होंगे। कलेक्टर को अपने बीच सहज रूप में देखकर ग्रामीण और युवा उत्साहित नजर आए।

संक्षिप्त समाचार

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान, 42 विमान और ड्रोन तबाह होने का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की ओर से 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कम से कम 42 सैन्य विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। यह जानकारी अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च एजेंसी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक आधिकारिक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इन विमानों में लड़ाकू जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं। सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जिन विमानों को नुकसान पहुंचा या जो नष्ट हुए(कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने यह आंकड़े अमेरिकी रक्षा विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयानों व मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए हैं। सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस और उसकी समितियों को नीति और कानूनी मामलों पर विश्लेषण उपलब्ध कराती है। इसी बीच, 12 मई को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विनियोग उपसमिति की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक पेंटागन नियंत्रक जूल्स डब्ल्यू हर्स्ट ने बताया कि ईरान में सैन्य अभियानों की लागत का अनुमान बढ़कर 29 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लागत में इस बड़े इजाफे की प्रमुख वजह सैन्य उपकरणों की मरम्मत और उनके प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) का संशोधित आकलन है। हर्स्ट ने कहा कि इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा उपकरणों की मरम्मत या उन्हें बदलने की लागत के अधिक सटीक अनुमान से आया है।

अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी-राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, मैक्रों के निमंत्रण से चर्चाएं तेज

पेरिस, एजेंसी। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात

हो सकती है। यह मुलाकात फ्रांस में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो 16 महीनों से भी ज्यादा समय के बाद दोनों नेता पहली बार आमने–सामने होंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस संभावित मुलाकात पर टिकी हैं। फ्रांस के एवियन–लेस–बैंस में 15 से 17 जून तक 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। हालांकि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी एक महत्वपूर्ण भागीदार देश के तौर पर भारत को बुलाया गया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने फरवरी में भारत दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में आने का न्योता दिया था। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में इस यात्रा की पुष्टि की है। इस बीच फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, जीन–नोएल बैरोट ने आज अब्बे डेस वॉक्स–डे–सर्ने में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एवियन शिखर सम्मेलन (15–17 जून) में अपनी भागीदारी की पुष्टि का स्वागत किया। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में भारत के योगदान की सराहना की। इस बैठक के दौरान पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और ट्रंप के इस संभावित मुलाकात पर टिकी हैं। ट्रंप भी जी7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा वहीं इस बीच, अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 से 17 जून तक फ्रांस में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

पीएम मोदी पर नस्लीय कार्टून बनाने पर विवाद; निशाने पर आया नॉर्वे का अखबार

ओस्ला, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान प्रेस स्वतंत्रता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच नॉर्वे के प्रमुख अखबार में प्रकाशित एक कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। इस कार्टून में पीएम मोदी को सपेरे के रूप में दिखाया गया था, जिसे लेकर कई लोगों ने अखबार पर नस्लीय और रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

यह कार्टून पीएम मोदी के ओस्लो पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले प्रकाशित किया गया था। इसे अखबार के एक ओपिनियन आर्टिकल के साथ छापा गया, जिसकी हेडलाइन का अनुवाद एक चतुर लेकिन परेशान करने वाला व्यक्ति बताया गया। लेख में इस बात पर चर्चा की गई थी कि भारत की नजर नॉर्डिक देशों पर क्यों है। वहीं कार्टून में मोदी को सपेरे के रूप में दिखाया गया, जबकि सांप की जगह पेट्रोल पंप की फ्यूल पाइप दिखाई गई थी।

सोशल मीडिया पर आई तीखी प्रतिक्रिया: कार्टून सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने इसे भारत की पुरानी और अपमानजनक पश्चिमी छवि से जोड़कर देखा। लंबे

समय तक पश्चिमी मीडिया में भारत को 'सांप सपेरों, हाथियों और अंधविश्वासों का देश' बताने वाली छवियों का इस्तेमाल होता रहा है। स्नेक चार्मर यानी सांप सपेरा वाली छवि को हाल के वर्षों में कई विशेषज्ञों और आलोचकों ने नस्लीय और जेनोफोबिक प्रतीक करार दिया है।

विदेशी मीडिया में अक्सर दिखाई देती है नस्लीय सोच: यह पहला मौका नहीं है जब किसी विदेशी मीडिया संस्थान ने भारत को इस तरह दर्शाया हो। अक्तूबर 2022 में स्पेन के अखबार ने भारत की आर्थिक तरक्की को दिखाने के लिए सांप सपेरे की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। उस समय भी इस चित्रण को लेकर काफी आलोचना हुई थी।

पीएम मोदी ने नस्लीय सोच के खिलाफ की थी टिप्पणी: खास बात यह है कि पीएम मोदी खुद भी पहले इस मुद्दे पर टिप्पणी कर चुके हैं। 2014 में अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत अब स्नेक चार्मर्स का देश नहीं, बल्कि माउस चार्मर्स का देश बन चुका है। उनका इशारा कंप्यूटर माउस और भारत की तकनीकी प्रगति की ओर था। इससे पहले जनवरी 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात युवा सम्मेलन में भी उन्होंने कहा था कि दुनिया की नजर में भारत की छवि सांप सपेरों के देश से बदलकर तकनीक और नवाचार वाले देश की बन रही है।

इसी दौरान नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर भी एक अलग विवाद सामने आया। पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के संयुक्त बयान के दौरान एक पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन पीएम बिना सवाल लिए वहां से निकल गए। इसके बाद नॉर्वे की पत्रकार और कमेंटेटर हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में पीएम मोदी संयुक्त बयान के बाद मंच से जाते दिखाई देते हैं। पोस्ट में पत्रकार ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? गौरतलब है कि नॉर्वे इस समय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर है, जबकि भारत की रैंकिंग 154 से गिरकर 157 पर पहुंच गई है। इसी मुद्दे ने बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में भी बहस का रूप ले लिया। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान हेले लिंग ने भारत में कथित मानवाधिकार उल्लंघन और प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करे। इसके जवाब में भारतीय राजनयिक सिबी जॉर्ज ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार है। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत का हवाला देते हुए कहा कि यही भारत की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

रोमियो-जूलियट कानून? नेपाल में बड़े बदलाव की तैयारी में बालेन सरकार, किशोरों के प्यार से जुड़ा है मामला

काठमांडु , एजेंसी। नेपाल की बलेन शाह सरकार रेप कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार रोमियो-जूलियट क्लॉज लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कम उम्र के किशोर-किशोरियों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को अपने आप रेप का मामला नहीं माना जाएगा।

प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक, 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के बीच यदि उम्र का अंतर तीन साल तक है और रिश्ता आपसी सहमति से है, तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हालांकि यौन शोषण, दबाव या जबरदस्ती के मामलों में सख्त सजा जारी रहेगी। नेपाल के मौजूदा कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध को, सहमति होने के बावजूद, रेप माना जाता है। वहीं देश में शादी की कानूनी उम्र 20 साल तय है।

आलोचकों का कहना है कि मौजूदा कानून की वजह से कई ऐसे मामले सामने आए, जहां आपसी सहमति से रिश्ते में रहने वाले किशोर लड़कों को जेल जाना पड़ा। कई मामलों में परिवारों ने रिश्ते का विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, खासकर अंतरजातीय संबंधों या घर से भागकर शादी करने वाले मामलों में।

इसी बीच नेपाल में शादी की कानूनी उम्र 20 से घटाकर 18 साल करने पर भी बहस चल रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर समाज में अलग-अलग राय सामने आ रही हैं।

अदालतों तक पहुंचे कई विवादित मामले: नेपाल के कानून सचिव उदय राज धुंगाना ने कहा कि किशोर जोड़ों से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार रोमियो और जूलियट कानून तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य रेप कानून को कमजोर करना नहीं है, बल्कि शोषण और किशोरों के स्वाभाविक रिश्तों के बीच फर्क करना है।

राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

सियोल, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित सियोल नेशनल सेमेट्री पहुंचकर देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने विशेष रूप से कोरियाई युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को याद करते हुए राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और मौन रखकर सम्मान प्रकट किया। सियोल नेशनल सेमेट्री दक्षिण कोरिया के उन सैनिकों और नागरिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। यह स्मारक राष्ट्रीय सम्मान, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। वह मंगलवार को दक्षिण कोरिया पहुंचे थे, जहां भारत के राजदूत गौरंगलाल दास और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह 18 से 21 मई तक दो देशों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में उन्होंने 18 और 19 मई को वियतनाम का दौरा किया, जिसके बाद वह दक्षिण कोरिया पहुंचे। इस बहु–देशीय यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। दौरे से पहले रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि उनकी यात्रा का मुख्य फोकस रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा उद्योग साझेदारी को मजबूत बनाना और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

ताइवान ने लगे भारत विरोधी पोस्टर: इलैक्शन उम्मीदवार की शर्मनाक टिप्पणी- भारतीय मजदूरों को मत लाओ वे...

ताइपे, एजेंसी। ताइवान में स्थानीय चुनाव के दौरान भारतीयों को लेकर विवादित पोस्टर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति की तस्वीर पर बड़ा नो का निशान बनाया गया था। पोस्टर में भारतीय प्रवासी मजदूरों का विरोध करते हुए उन्हें अपराधी बताया गया। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और ताइवान के बीच हुए श्रम सहयोग समझौते के तहत भारतीय कामगारों को ताइवान भेजने की तैयारी चल रही है। इस समझौते के तहत इस साल के अंत तक करीब 1000 भारतीय मजदूर ताइवान पहुंच सकते हैं। ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिनतांग के कुछ नेताओं ने भी भारतीय मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। सांसद हुआंग चिएन-पिन ने भारत के अपराध संबंधी आंकड़ों का हवाला देते हुए संसद में कहा कि भारतीय कामगारों की सख्त जांच और निगरानी होनी चाहिए। उनके बयान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। ताइवान में रहने वाले भारतीयों और कई स्थानीय नेताओं ने इन पोस्टरों और बयानों को नस्लीय भेदभाव बताया है। आलोचकों का कहना

है कि किसी नीति का विरोध अलग बात है, लेकिन किसी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को निशाना बनाना गलत है। वांग यी-हेंग ने कहा कि पगड़ी केवल कपड़ा नहीं बल्कि सिख आस्था और सम्मान का प्रतीक है।

उन्होंने पोस्टर को अज्ञानता और भेदभाव से भरा कदम बताया।ताइवान में फिलहाल करीब 7000 भारतीय रहते हैं, जिनमें अधिकतर हाई-टेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं। दरअसल ताइवान लंबे समय से श्रमिक संकट का सामना कर रहा है। वहां जन्म दर घट रही है और बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। इसी वजह से ताइवान पहले से इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड से मजदूर बुलाता रहा है। अब भारत को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

हालांकि ताइवान में फ्यूजिटिव वर्कर्स यानी काम छोड़कर अवैध रूप से रहने वाले विदेशी मजदूरों की समस्या को लेकर भी चिंता है। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि विदेशी श्रमिकों पर सख्त निगरानी जरूरी है। इससे पहले भी विवाद हुआ था जब ताइवान की पूर्व श्रम मंत्री हसू मिंग-चुन ने कहा था कि शुरुआत में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से मजदूर बुलाए जा सकते हैं क्योंकि उनकी जीवनशैली और खानपान ताइवान से ज्यादा मेल खाते हैं। इस बयान की भी नस्लवादी टिप्पणी के रूप में आलोचना हुई थी, जिसके बाद ताइवान सरकार को माफी मांगनी पड़ी थी।

टेक्सस में टेस्ला साइबर ट्रक को जानबूझकर झील में उतारा

वेड मोड टेस्ट के दौरान गाड़ी आंशिक रूप से डूब गई

चालक जिमी जैक मैकडैनियल को ग्रेपवाइन जेल भेजा गया

वाशिंगटन एजेंसी। अमेरिका के टेक्सस में टेस्ला साइबर ट्रक के एक मालिक को सोमवार की रात जेल जाना पड़ा। दरअसल, मामला यह है कि उसने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को ग्रेपवाइन झील में उतार दिया था ताकि वह उसके वेड मोड फीचर को टेस्ट कर सके।

ग्रेपवाइन पुलिस के अनुसार, शाम करीब 8 बजे (स्थानीय समय) के आसपास, केटीज वुड्स बोट रैंप पर अधिकारियों और दमकलकर्मियों को बुलाया गया, क्योंकि उन्हें पानी में एक गाड़ी के होने की रिपोर्ट मिली थी। वहीं, जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें साइबर ट्रक किनारे के पास आंशिक रूप से डूबा हुआ मिला। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। इसके साथ ही जब ट्रक डूबने लगा, तो उनमें से एक ने मजाक में कहा, आप यहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने जान-बूझकर ट्रक को झील में उतारा था ताकि वह वेड मोड का इस्तेमाल कर सके। यह साइबरट्रक की ऑफ-रोड सेटिंग्स में से एक है। टेस्ला के अनुसार, इस मोड का इस्तेमाल उथले पानी में धीरे-धीरे गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है। ग्रेपवाइन पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, पानी में गाड़ी को लेकर जाने से वह खराब हो गई और उसमें पानी भर गया।

हालांकि, इस दौरान ड्राइवर और यात्री गाड़ी छोड़कर बाहर निकल आए, और ग्रेपवाइन दमकल विभाग की जल बचाव टीम ने गाड़ी को झील से बाहर निकालने में मदद की। ग्रेपवाइन जेल में बंद है ड्राइवर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर की पहचान जिमी जैक मैकडैनियल के रूप में हुई है। फिलहाल उसे ग्रेपवाइन जेल में बंद कर दिया गया है। उस पर पार्क या झील के बंद हिस्से में गाड़ी चलाने, बिना वैध बोट रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने, और पानी में सुरक्षा से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

टेस्ला की मालिक नियमावली में ड्राइवरों को चेतावनी दी गई है कि वे पानी में उतरने से पहले वहां के हालात की जांच कर लें। साथ ही, उन्हें गहरे या तेज बहाव वाले पानी में गाड़ी न चलाने की भी हिदायत दी गई है, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मौजूदा कहानी एक बार फ़िर दर्शकों को इंसानियत और आपसी सहयोग का महत्व समझा रही है

इस ट्रैक में रोशन सिंह सोढ़ी के एक दोस्त ने 15 दिनों के लिए सुरक्षित रखने हेतु उन्हें 1 लाख रुपये दिए होते हैं। लेकिन मिसेज रोशन सोढ़ी, कई वर्षों से परिचित एक फ्ल विक्रेता की अचानक आर्थिक मदद की जरूरत को देखते हुए, वह रकम उसे दे देती हैं। फ्ल विक्रेता तीन दिन में पैसे लौटाने का वादा करता है, लेकिन 15वें दिन तक भी वह रकम का इंतजाम नहीं कर पाता। उसी रात सोढ़ी का दोस्त पैसे लेने आने वाला होता है, जिससे मिसेज सोढ़ी की परेशानी बढ़ जाती है। आखिरकार वह गोकुलधाम सोसायटी की महिला मंडल से मदद मांगती हैं और सभी महिलाएं तुरंत उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। यह कहानी गोकुलधाम सोसायटी की महिलाओं के जरिए एकता, दया और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश करती है। आज के समय में, जब लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पड़ोसियों से भी दूरी बढ़ती जा रही है, तब यह कहानी एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है कि मुश्किल समय में एक–दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। भावनात्मक और वास्तविकता से जुड़ी यह कहानी दर्शकों को भरोसा, अपनापन और सहानुभूति से भरा समाज बनाने की प्रेरणा देती है। गोकुलधाम की महिलाएं यह साबित करती हैं कि साथ और सहयोग हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान हो जाती है। यह ट्रैक निर्माता आसित कुमार मोदी की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें मनोरंजन के साथ–साथ भारतीय संस्कारों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सार्थक कहानियां दिखाई जाती हैं। ञ्ख्व्ह्रष्ट ने हमेशा सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि सकारात्मकता, रिश्तों की गर्माहट और एकजुटता का संदेश भी दर्शकों तक पहुंचाया है।

ओप्पो इंडिया ने अपनी फाईंड एक्स9 सीरीज़ में नैक्स्ट जनरेशन इमेजिंग और ए. आई अनुभव उपलब्ध कराए

नई दिल्ली: आज ओप्पो इंडिया ने भारत में फाईंड एक्स९एस और फाईंड एक्स9 अल्ट्रा का लॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ है, जो क्रिएटर्स को एडवांस्ड इमेजिंग, ए.आई अनुभव और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस प्रदान करता है। ओप्पो फाईंड एक्स९एस सनसेट ऑरेंज, लैवेंडर स्काई और मिडनाईट ग्रे कलर्स में, तथा फाईंड एक्स9 अल्ट्रा टुंड्रा अंबर और केनयन ऑरेंज रंगों में उपलब्ध है।ये दोनों स्मार्टफोन 28 मई से ओप्पो ई–स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मेनलाईन रिटेल स्टोर्स से खरीदे जा सकेंगे। गोल्डी पटनायक, हेड, कम्युनिकेशंस, ओप्पो इंडिया ने कहा, ''ओप्पो में हम इनोवेशन के लिए अपना ध्यान इस पर केंद्रित करते हैं कि लोग अपनी डिवाईस का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

खुद चुनाव हारकर 'रीढ़विहीन' हो चुके नेता एक-दूसरे को ज्ञान बाँट रहे : भाजपा

प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू का तीखा कटाक्ष : बैज और सिंहदेव के बीच छिड़ी 'नूराकुश्ती' ने साबित किया कि कांग्रेस को जनता से नहीं, सिर्फ पद से सरोकार

मूक पत्रिका/रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और 'कुर्सी की सिरफुटौव्वल' पर तीखा कटाक्ष किया है। श्रीमती साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चल रही बयानबाजी को बेहद हास्यास्पद बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब 'हारी हुई तिकड़ी' का ऐसा अखाड़ा बन चुकी है,

जहां हर कोई अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक–दूसरे को धकेलने में लगा है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि बैज की सिंहदेव को दिल्ली जाने और युवाओं को मौका देने की नसीहत असल में युवाओं के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि अपनी छिनती हुई कुर्सी को बचाने का डर और छटपटाहट है। बैज भली–भाँति जानते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए वे अब वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ से 'तड़ीपार' कर दिल्ली भेजने की राजनीति कर रहे हैं। ?श्रीमती साहू ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सिंहदेव के पलटवार पर तंज कसते हुए कहा कि सिंहदेव का यह कहना कि वे चुनाव हारे हैं और बैज भी चुनाव हारे हैं, कांग्रेस की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। जनता द्वारा पूरी तरह नकारे जा चुके ये नेता अब आपस में ही यह प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा 'फ्लॉप' है? सिंहदेव जिस तरह कुर्सी के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस में सेवा की नहीं, सिर्फ मलाईदार पद हथियाने की होड़ मची है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका, उसके नेता अपनी कमियों पर आत्ममंथन करने के बजाय एक–दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त हैं। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब ढाई–ढाई साल के मुख्यमंत्री के खेल ने प्रदेश को बर्बाद किया और आज जब ये विपक्ष में हैं, तब भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नूराकुश्ती जारी है। श्रीमती साहू ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की पहली और आखिरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार और संगठन के चेहरों को चमकाना है, जनता की भलाई से इनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ की जनता इस सर्कस को बड़े गौर से देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस के इस बचे–खुचे वजूद को भी समाप्त कर देगी।

शायद समझ नहीं आएगी... पर याद रह जाएगी: कलर्स पेश करता है 'जूही मुई', जिसमें ईशा सिंह मुख्य भूमिका निभा रही हैं

दुनिया हमेशा एक ख़ास तरह की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करती आई है यह मानते हुए कि प्रतिभा को शब्दों में ढाला जाना चाहिए और आत्मविश्वास को ज़ोर से जताना चाहिए। लेकिन कुछ दिमाग़ ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में शामिल नहीं होते वे भावनाओं से ज़्यादा तर्क पर चलते हैं, मनाने से ज़्यादा सटीकता पर भरोसा करते हैं और सामाजिक दिखावे से ज़्यादा सच्चाई को अहमियत देते हैं। इसी अनदेखी दुनिया को कलर्स अपने नए शो 'जूही मुई' के प्रोमो के ज़रिए सामने ला रहा है, जिसमें ईशा सिंह मुख्य किरदार निभा रही हैं। यह सोचने पर मजबूर कर देने वाला ड्रामा जूही सूरी की कहानी है एक प्रतिभाशाली लड़की जिसका असाधारण दिमाग़ उन पैटर्न्स और सच्चाइयों को पकड़ लेता है जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। पिता की लीगल प्रैक्टिस के माहौल में पलीबढ़ी जूही की यह अनोखी बुद्धिमत्ता क़ानून की दुनिया में उसकी सबसे बड़ी ताक़त बन सकती है। लेकिन एक ऐसे समाज में जहाँ शोर और जल्दबाज़ी से फैसले लिए जाते हैं।

लिटन दास और रिजवान भिड़े! बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने किया जमकर स्लेज

सिलहट, एजेंसी। बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को अपनी सरजमीं पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। ढाका में पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 104 रन से और सिलहट में दूसरे टेस्ट में 78 रन से जीत हासिल की। हालांकि, सिलहट टेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बांग्लादेश के लिटन दास और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान भिड़ गए। और इसके बाद तो पूरी बांग्लादेश टीम ने मिलकर रिजवान को खूब स्लेज किया। बांग्लादेश क्रिकेटरों ने यहां तक कहा कि रिजवान अच्छी एक्टिंग करता है, इसे बॉलीवुड में भेजो, लेकिन वहां भी इसे कोई नहीं लेगा। इसकी ओवरएक्टिंग इतनी है कि 50 पैसे काट लेंगे।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 437 रन का लक्ष्य दिया था। रिजवान और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की लड़ाई पाकिस्तान की दूसरी पारी के दौरान हुई।

वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ब्राजील को झटका; नेमार जूनियर फिर हुए चोटिल

रियो डी जनेरियो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज से ठीक पहले ब्राजील को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। नेमार को हाल ही में ब्राजील की विश्व कप टीम में चुना गया है। 'शिन्हुआ' की रिपोर्ट के मुताबिक, 34 साल के सैंटोस स्टार बुधवार को सैन लोरेंजो के खिलाफ अपनी टीम के घरेलू कोपा सुदामेरिकाना मैच में पिंडली की चोट के कारण नहीं खेल पाए। हालांकि ब्राजील के क्लब ने नेमार की इंजरी को गंभीर नहीं बताया है। सैंटोस टीम के डॉक्टर रोड्रिगो जोगैब ने कहा कि फॉरवर्ड खिलाड़ी 27 मई को ब्राजील के पहले प्री-वर्ल्ड कप ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार होंगे।

'ओ ग्लोबो' ने जोगैब के हवाले से कहा, 'नेमार नेशनल टीम में फिट या लगभग पूरी तरह से फिट होने की स्थिति में ही टीम को रिपोर्ट करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि वह अगले मंगलवार को डेपोर्टिवो कुएनका के खिलाफ खेल सकते हैं।' ब्राजील के लिए 128 इंटरनेशनल मुकाबलों में सबसे ज्यादा 79 गोल करने वाले नेमार ने ब्राजील के लिए आखिरी मुकाबला अक्टूबर 2023 में खेला था।

उरुग्वे के खिलाफ हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में उनका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फट गया था। बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व अटैकर तब से चोटों से जूझ रहे हैं; पिछले साल जनवरी में अपने बचपन के क्लब सैंटोस में लौटने के बाद नेमार ने 38 मुकाबलों में सिर्फ 17 गोल किए हैं।

यह नेमार का चौथा फीफा वर्ल्ड कप होगा। इससे पहले वह 2014, 2018 और 2022 एडिशन में खेल चुके हैं। वह कैस्टिलो, जल्मा सैंटोस, निल्टन सैंटोस, पेले, एमर्सन लीओ, कैफू, रोनाल्डो और थियागो सिल्वा के साथ सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट में खेलने वाले ब्राजील के खिलाड़ी बन जाएंगे।नेमार के पास पेले के साथ जुड़ने और चार अलग-अलग वर्ल्ड कप में ब्राजील की नंबर 10 शर्ट पहनने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने का भी मौका है। विश्व कप में नेमार ने 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने आठ गोल किए हैं और तीन असिस्ट किए हैं। ब्राजील अपने अभियान का आगाज 13 जून को न्यू जर्सी में मोरक्को के खिलाफ टूर्नामेंट शुरू करेगा, जिसके बाद ग्रुप सी में टीम की भिड़ंत हैती और स्कॉटलैंड से होगी।

वैभव सूर्यवंशी अब अभिषेक से आगे

रोहित शर्मा 4 नंबर पर

आईपीएल में 200+ चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा ओपनर बैटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 64वें मैच में चेज करते हुए 93 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वैभव ने अपनी इस पारी के दौरान 10 बेहतरीन छक्के भी लगाए और वो अब आईपीएल इतिहास में 200 या उससे ज्यादा स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए और अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

वैभव सूर्यवंशी निकले अभिषेक शर्मा से आगे- आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर थे, लेकिन लखनऊ के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाकर वैभव

सूर्यवंशी ने अब अभिषेक को पीछे छोड़ दिया। आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब वैभव पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने अब तक इस लीग में चेज करते हुए 10 पारियों में कुल 42 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने 17 पारियों में 41 छक्के लगाए थे। आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने अब तक 15 पारियों में कुल 40 छक्के लगाए हैं जबकि रोहित शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 25 पारियों में 38 छक्के जड़े हैं। केएल राहुल इस लिस्ट में 5वें भारतीय हैं जिन्होंने 200 या उससे ज्यादा का स्कोर चेज करते हुए इस लीग में 22 पारियों में कुल 36 छक्के लगाए हैं।

200 या उससे ज्यादा स्कोर चेज करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले

टॉप-5 भारतीय

- 42 छक्के : वैभव सूर्यवंशी (10 पारी)
- 41 छक्के : अभिषेक शर्मा (17 पारी)
- 40 छक्के : संजू सैमसन (15 पारी)
- 38 छक्के : रोहित शर्मा (25 पारी)
- 36 छक्के : केएल राहुल (22 पारी

दलीप ट्रॉफी से होगी BCCI के घरेलू सत्र की शुरुआत

11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी का पहला चरण

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2026-27 घरेलू सत्र के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। नए घरेलू सीजन की शुरुआत 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी के साथ होगी, जबकि देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी इस बार भी दो चरणों में आयोजित की जाएगी। रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से खेला जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी समेत पूरे घरेलू सत्र का शेड्यूल भी सामने आ गया है। बीसीसीआई इस घरेलू सत्र में पुरुष और महिला वर्ग के अलग-अलग आयु समूहों और सीनियर स्तर पर कुल 1788 मुकाबलों का आयोजन करेगा। इसमें पुरुषों के अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर टूर्नामेंट शामिल हैं, जबकि महिलाओं के अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर स्तर की प्रतियोगिताएं भी खेली जाएंगी।

दलीप ट्रॉफी फिर जोनल फॉर्मेट में- दलीप ट्रॉफी की वापसी फिर जोनल फॉर्मेट में होगी। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक खेला जाएगा।

सभी मुकाबले बेंगलुरु स्थित ब्बष्टद्ध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होंगे। इसके बाद रणजी ट्रॉफी विजेता जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के बीच ईरानी कप एक से पांच अक्टूबर तक श्रीनगर में खेला जाएगा।

दो चरणों में रणजी ट्रॉफी-

बीसीसीआई के घरेलू कैलेंडर की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से पांच नवंबर तक खेला जाएगा। इस दौरान चार राउंड के मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट का दूसरा चरण 17 जनवरी से तीन मार्च 2027 तक आयोजित होगा। इसके बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएंगी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी

राष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 14 नवंबर से छह दिसंबर तक खेली जाएगी। लीग चरण के मुकाबले मुंबई, मोहाली, विशाखापत्तनम और कोलकाता में होंगे, जबकि नॉकआउट मुकाबले नागपुर में खेले जाएंगे। बीसीसीआई के अनुसार, इस टूर्नामेंट का समय ऐसा रखा गया है ताकि आईपीएल नीलामी से पहले टैलेंट स्काउट खिलाड़ियों पर नजर बना पाएं और अपनी सूची तैयार कर सकें। आईपीएल नीलामी दिसंबर में होने की संभावना है।

दिसंबर में विजय हजारे ट्रॉफी

राष्ट्रीय वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 14 दिसंबर 2026 से आठ जनवरी 2027 तक खेली जाएगी। बीसीसीआई ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर- 16) के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। यह टूर्नामेंट नवंबर से जनवरी के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी का समय मिलेगा। इसके साथ ही स्कूल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को फरवरी-मार्च में होने वाली वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2026-27 घरेलू सत्र का कार्यक्रम सभी प्रारूपों और आयु वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू ढांचे को आगे बढ़ाने की दिशा में तैयार किया गया है।

प्लेऑफ की उम्मीदें अब भी बरकरार

मुंबई पर जीत के बाद तालिका में छठे स्थान पर पहुंची कोलकाता

कोलकाता, एजेंसी। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा है। बुधवार को ईडन गार्डन्स पर खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में

केकेआर ने 18.5 ओवर में छह विकेट पर 148 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

इस जीत के साथ कोलकाता की टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है। उनके खाते में 13 अंक हो गए और नेट रन रेट +0.011 हो गया है। अब केकेआर को उनका आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है। कोलकाता ने इस जीत के दम पर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा है।

मुंबई ने 41 के स्कोर तक अपने चार विकेट खो दिए थे। जब पारी के आठ ओवर पूरे हो गए थे, बारिश ने दखल दिया, लेकिन ब्रेक के बावजूद ओवरों में कटौती नहीं की गई। कप्तान हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ पांचवें विकेट के लिए 49 गेंदों में 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। तिलक वर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पांड्या ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

कॉर्बिन बॉश ने दीपक चाहर के साथ आठवें विकेट के लिए 20 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। बॉश 18 गेंदों में दो छक्कों और तीन चौकों के साथ 32 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि सुनील नरेन ने एक विकेट निकाला।

इसके जवाब में केकेआर ने पहले ही ओवर में फिन एलन (8) का विकेट गंवा दिया। यहां से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मनीष पांडे के साथ 28 गेंदों में 38 रन की साझेदारी की। रहाणे 17 गेंदों में 4 चौकों के साथ 21 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद कैमरन ग्रीन (4) भी पवेलियन लौट गए। टीम ने 7.1 ओवरों में 54 के स्कोर तक अपने तीन विकेट खो दिए थे। यहां से रोवमैन पॉवेल ने मनीष पांडे के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।

भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया

भोपाल। भारतीय अंडर-18 महिला हॉकी टीम ने बुधवार को उद्धव दास मेहता (भाई जी) सेंट्रल साई सेंटर में सीरीज के चौथे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्वार्टर की शुरुआत में ही ऑरोरा कोवासेविच (8') के गोल से बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने जल्द जवाब दिया और कप्तान स्वीटी कुजूर (13') ने शुरुआती क्वार्टर खत्म होने से पहले पहला गोल कर टीम को बराबरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारत की दीया (25') ने गोल दागा। इस गोल से भारतीय टीम हाफटाइम तक 2-1 से आगे रही।

भारतीय टीम ने दूसरे हाफ में नियंत्रण बनाए रखा और तीसरे क्वार्टर में प्रियंका मिंज (44') के गोल से अपनी बढ़त 3-1 की कर ली। नौशीन नाज (50') ने आखिरी क्वार्टर में एक और गोल किया और भारत की बढ़त 4-1 करते हुए जीत पक्की कर दी।

भारतीय टीम के लिए यह जीत बहुत अहम रही। इस जीत के बाद इस महीने के आखिर में जापान में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

हालांकि 4 मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-3 से जीत दर्ज की।सीरीज के पहले मैच में भारत को 3-4 से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 1-2 से हराया था।

भारतीय टीम को निश्चित रूप से शुरुआती तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलयाई टीम को मैचों के दौरान मुश्किल में रखा। पहला और तीसरा मुकाबला बेहद कांटे वाला रहा।

प्लेऑफ का गणित: राजस्थान की किस्मत अपने हाथ

3 टीमें दूसरों पर निर्भर, दिल्ली का बाहर होना तय

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लीग स्टेज में पांच मैच बाकी हैं और 5 टीमें प्लेऑफ की में जगह बनाने की रेस में हैं। हालांकि,असलियत में केवल चार टीमों के पास ही प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना है। दिल्ली कैपिटल्स का रनरेट इतना खराब है कि वह शायद ही प्लेऑफ में पहुंच पाए। बाकी चार टीमों में राजस्थान रॉयल्स की किस्मत अपने हाथ में है। पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत अन्य मुकबालों पर निर्भर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत का मतलब यह भी है कि लीग स्टेज के आखिरी दिन 24 मई से पहले प्लेऑफ की जगह तय नहीं होगी।

आइए जानते हैं प्लेऑफ में पहुंचने का गणित

- **राजस्थान रॉयल्स : मैच -14, अंक-14**- लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अन्य मुकाबलों पर निर्भर नहीं रहना है। अगर राजस्थान रविवार को मुंबई इंडियंस को हरा देती हैं तो वह दूसरे 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद आखिरी मुकाबला हार जाती हैं तो राजस्थान टॉप-2 में भी पहुंच सकता है। हालांकि, रनरेट को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम है।

- **पंजाब किंग्स : 13 मैच में 13 अंक**- पंजाब किंग्स को न सिर्फ अपने आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना है, बल्कि उन्हें यह भी उम्मीद करनी है कि राजस्थान रॉयल्स से मुंबई इंडियंस जीत जाए और कोलकाता नाइट राइडर्स बेहतर रनरेट के साथ 15 अंक तक न पहुंचे। अगर पंजाब किंग्स शनिवार को जीतती है। राजस्थान अपना आखिरी गेम हार जाती है, और कोलकाता आखिरी मैच जीत जाती है तो पंजाब किंग्स और केकेआर दोनों 15 अंक पर होंगी, इससे रनरेट पर मामला आ जाएगा।

- **चेन्नई सुपर किंग्स : मैच-13, अंक-12**- चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए कि पहले वह गुजरात टाइटंस को हराए। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आखिरी मैच हार जाएं। वह रनरेट के मामले में राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ सकती है। दिल्ली कैपिटल्स का रनरेट बहुत खराब है। वह शायद ही चेन्नई सुपर किंग्स से आगे निकल पाए।

- **कोलकाता नाइट राइडस : मैच-13, अंक-13**- कोलकाता नाइट राइडर्स को रनरेट पर निर्भर रहे बिना प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी मैच जीतना होगा। यह उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आखिरी मैच हार जाएं। राजस्थान रॉयल्स जीती तो कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर होगी। अगर पंजाब किंग्स जीती तो दोनों के 15-15 अंक होंगे।
- **दिल्ली कैपिटल्स : मैच-13, अंक 12**- लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत से दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंक तक न पहुंच पाएं तो भी राजस्थान रॉयल्स से रनरेट के मामले में दिल्ली कैपिटल्स को आगे निकलने के लिए 230 रनों से जीत दर्ज करने की जरूरत होगी।

खरीफसीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण के नए नियम जारी

जमाखोरी पर लगेगी लगाम, किसानों को समय पर मिलेगा खाद

सक्ती/मूक पत्रिका

आगामी खरीफसीजन 2026 को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाड़ी देशों में चल रहे तनावपूर्ण हालातों के बीच किसानों को सही समय पर और समान मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने इस बार कड़े और व्यवस्थित नियम बनाए हैं। कृषि उप संचालक तरुण कुमार प्रधान ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किसानों को संतुलित खाद उपयोग, हरी खाद और जैव उर्वरकों जैसे नील हरित शैवाल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को मिलने वाले यूरिया और डीएपी की मात्रा पिछले खरीफ सीजन 2025 में प्राप्त खाद के आधार पर तय की जाएगी। किसानों को प्रारंभिक

चरण में पिछले वर्ष की कुल मात्रा का 80 प्रतिशत पारंपरिक यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत आपूर्ति उपलब्धता के अनुसार दी जाएगी, अन्यथा उसके स्थान पर नैनो यूरिया का विकल्प रहेगा। वहीं डीएपी पिछले वर्ष की मात्रा का केवल 60 प्रतिशत ही मिलेगा तथा शेष 40 प्रतिशत की पूर्ति वैकल्पिक एनपीके खाद या नैनो डीएपी के माध्यम से की जाएगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत खाद का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। यदि किसी प्रकार का अवैध भंडारण या गैर-कृषि कार्यों में उपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी किस्त पहली किस्त के 20 दिन बाद मिलेगी

बड़े कृषकों को 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर यूरिया तीन किस्तों में दिया जाएगा तथा प्रत्येक किस्त के बीच 20 दिनों का अंतर रहेगा। किसानों को मिलने वाली खाद की मात्रा की गणना बोरी संख्या के आधार पर की जाएगी। यदि गणना में दशमलव आता है तो उसे निकटतम पूर्ण संख्या में माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर 7.2 बोरी होने पर 7 बोरी और 7.8 बोरी होने पर 8 बोरी खाद प्रदान की जाएगी।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पूरी तरह वैकल्पिक

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो यूरिया या नैनो डीएपी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह किसान की इच्छा पर निर्भर रहेगा। खाद की कालाबाजारी रोकने और बड़े स्तर पर भंडारण पर नियंत्रण के लिए भूमि के आधार पर वितरण व्यवस्था तय की गई है। सीमांत कृषकों को 2.5 एकड़ तक निर्धारित खाद की पूरी मात्रा एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 2.5 से 5 एकड़ तक के लघु कृषकों को यूरिया दो किस्तों में दिया जाएगा।

पटवारी की पत्नी का वन अधिकार पट्टा निरस्त, ग्राम सभा प्रस्ताव के बाद जिला स्तरीय समिति ने लिया फैसला, 2.023 हेक्टेयर भूमि का मामला

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा निरस्तीकरण का मामला सामने आया है। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने ग्राम कुटरू निवासी साधना चिड़ियाम का व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र निरस्त कर दिया है। साधना चिड़ियाम एक पटवारी की पत्नी बताई जा रही हैं। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार साधना चिड़ियाम, पति भानुप्रताप चिड़ियाम को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कुटरू के खसरा एवं वन कम्पार्टमेंट नंबर 49/2 की 2.023 हेक्टेयर भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) मान्यता पत्र प्रदान किया गया था। बताया गया है कि उक्त भूमि के निरस्तीकरण के लिए ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति से अनुमोदन मिलने के बाद प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को भेजा गया। एक अप्रैल 2026 को आयोजित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में मामले की समीक्षा की गई। इसके बाद पूर्व में जारी व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। आदेश कलेक्टर एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष की ओर से 14 मई 2026 को जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि डीएफओ बीजापुर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम भैरमगढ़, अधीक्षक भू-अभिलेख तथा तहसीलदार भैरमगढ़-कुटरू को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

क्या है व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर खेती और उपयोग का अधिकार दिया जाता है। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) मान्यता पत्र जारी किया जाता है। नियमों के उल्लंघन या समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति इसे निरस्त भी कर सकती है।

भाजपा के प्रशिक्षण महाभियान का आगाज, कार्यकर्ताओं को दिए संगठन मजबूती के मंत्र

भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्र सेवा का माध्यम – लता उसेंडी

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के तहत शुक्रवार से दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर से पहुंचे वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यपद्धति, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को लेकर मार्गदर्शन दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उद्घाटन सत्र की मुख्य वक्ता भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।उन्होंने संगठन की मजबूती, अनुशासन, सेवा कार्य, बूथ

सशक्तिकरण और जनसंपर्क को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कार्यकर्ताओं से सक्रियता के साथ जनता के बीच जाकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही।प्रशिक्षण वर्ग में संगठनात्मक संरचना, सोशल मीडिया की भूमिका, राष्ट्रवादी विचारधारा और कार्यकर्ता विकास जैसे विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकट, प्रदेश प्रवक्ता टिकेश्वर जैन, प्रदेश वक्ता शिवनारायण पांडेय, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य किरण उसेंडी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार और संगठन प्रभारी दीपेश अरोरा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने की। कार्यक्रम की रूपरेखा जिला महामंत्री फूलचंद गागड़ा ने संभाली। प्रशिक्षण में जिलेभर से भाजपा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

बूथ सशक्तिकरण और सोशल मीडिया पर विशेष फोकस

दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, जनसंपर्क अभियान और सेवा गतिविधियों के जरिए संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

सेवा सेतु पोर्टल बन रहा सुशासन का मजबूत माध्यम,पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार, नागरिकों को घर के नजदीक मिल रही सुविधाएं

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में ÷सेवा सेतु÷ पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल सुशासन की इस अभिनव पहल के माध्यम से अब जांजगीर-चांपा जिले के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशन में सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों एवं संबंधित विभागीय कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना एवं आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही पोर्टल के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए जा रहे है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित आवेदन, श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं सहित विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूर्व में नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सेवा सेतु पोर्टल के जरिए नागरिक एक ही स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ई जिला प्रबंधक जिला ई गवर्नेंस श्री सुनील कुमार साहू ने बताया की लोक सेवा केंद्र अब सेवा सेतु केंद्र और ऑपरेटर सेवा सेतु प्रबंधक कहलाएँगे। जिले के सभी ब्लॉक के सचिवो को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब ग्राम पंचायत स्तर के विवाह प्रमाण पत्र,भवन अनुज्ञा,स्ट्रीट लाइट बदलने,आवश्यक साफ़ सफ़ाई व्यवस्था,नाम परिवर्तन संबंधी राजपत्र अधिसूचना जैसे सेवायें जो ऑफ्लाइन था उसे अब सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जा रहा है।इस पोर्टल को वाट्सएप से भी जोड़ा गया है अब घर बैठें नागरिक वाट्सएप के माध्यम से सेवाओं और आवेदन की जानकारी ले सकते हैं। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से लोगों को जिला एवं तहसील मुख्यालय तक बार-बार आने की आवश्यकता कम होगी। इससे ग्रामीण नागरिकों को समय की बचत के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिलेगी। सेवा सेतु केवल एक डिजिटल पोर्टल नहीं, बल्कि शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने वाला प्रभावी माध्यम है। ऑनलाइन आवेदन एवं ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनी है। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सेवा सेतु पोर्टल का अधिकाधिक उपयोग करें तथा ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाकर शासन की पारदर्शी एवं सरल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनें।

कलेक्टर ने पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने कंज्यूमर पंप संचालकों की ली बैठक

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में पेट्रोल एवं डीजल के औद्योगिक प्रायोजन हेतु कन्ज्यूमर पंप उपयोगकर्ता उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान की आयल कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने औद्योगिक प्रायोजन, वाणिज्यिक प्रायोजन हेतु प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि कन्ज्यूमर पंप संचालनकर्ता सीधे आयल कंपनी से पेट्रोल एवं डीजल की खरीदी कर उपयोग करें। रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पंप से पेट्रोल एवं डीजल की खरीदी न करें, ताकि आम जनता, गुड्स ट्रांसपोर्ट एवं कृषक वाहन को सुगमता से पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने ऐसे प्रतिष्ठानों की विशेष निगरानी तथा समीक्षा करने हेतु आयल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी संचालकों से आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सहयोग करने की अपील की। बैठक में जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू, कन्ज्यूमर पंप उपयोगकर्ता उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान की आयल कंपनी के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

राहुल गांधी के बयान के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका पुतला, भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादा तोड़ने का आरोप

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के विरोध में भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विधायक चौक में जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पुतला दहन किया। कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।जिला महामंत्री फूलचंद गागड़ा ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में लगातार मिल रहे जनादेश से कांग्रेस और राहुल गांधी बौखला गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनता द्वारा लगातार नकारे जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की भाषा और व्यवहार में असंतुलन दिखाई दे रहा है।इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, कोषाध्यक्ष सोनल गुप्ता, वेंकट यालम, मिथलेश नाग, बलदेव उरसा, विकास कोड़े, दीपेश यालम, संतोष पुारी सहित भाजयुमो के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की।भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने भी राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अराजक मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में मर्यादा और सामाजिक सद्भाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान इन मूल्यों के विपरीत है। नाग ने कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस नेताओं में हताशा साफझलक रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नक्सलवाद के उन्मूलन, देश की सीमाओं की रक्षा और तिरंगे की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाना देशद्रोह की श्रेणी में आता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीद्ध के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाली भी है।

नशे में वाहन चलाने पर अदालत का सख्त रुख, जुर्माने के साथ 15 दिन की सामुदायिक सेवा

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, नशा किया तो सड़क पर उतरकर सुधार करना होगा

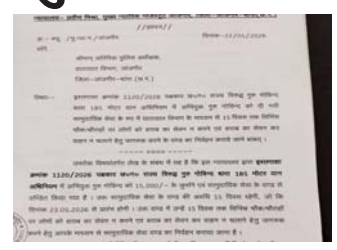

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर प्रवीण मिश्रा की अदालत ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का दंड सुनाया है। प्रकरण क्रमांक 1120/2026 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम गुरु गोविंद) में अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अभियुक्त को 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। यह सेवा दिनांक 23 मई 2026 से प्रारंभ होगी। अदालत के आदेशानुसार अभियुक्त को प्रतिदिन जिले के विभिन्न चौकङ्चौराहों पर आम नागरिकों को शराब का सेवन न करने एवं शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति जागरूक करना होगा। यह सामुदायिक सेवा यातायात विभाग जांजगीर के माध्यम से कराई जाएगी।न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियुक्त प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा में उपस्थित रहेगा।

उसकी उपस्थिति की नियमित पंजिका संधारित की जाएगी तथा सेवा अवधि पूरी होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।इस सामुदायिक सेवा की निगरानी के लिए उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री विजय पैकरा को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी स्तर पर आदेश के उल्लंघन की स्थिति में इसकी सूचना सीधे न्यायालय को दी जाएगी।न्यायालय के इस निर्णय को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे समाज में यह संदेश गया है कि नशे में वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आमजन के जीवन के लिए गंभीर खतरा भी है।

गांव-गांव पहुंचा विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों को सिखाई प्राकृतिक खेती

96 शिविरों में वैज्ञानिक खेती, जैविक उत्पाद और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

बीजापुर/आशिष पदमवार। जिले में किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती से जोड़ने के लिए कृषि एवं संवर्गीय विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के संयुक्त प्रयास से ÷विकसित कृषि संकल्प अभियान÷ चलाया गया। अभियान के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक खेती की जानकारी दी गई।अभियान का संचालन उप संचालक कृषि पीएस कुशरे, सहायक संचालक उद्यानिकी रामचन्द्र राव, उप संचालक पशुधन विकास विभाग राजीव शर्मा, सहायक संचालक मत्स्य विभाग मुकेश राघव और कृषि विज्ञान केन्द्र

के कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रमुख वैज्ञानिक अरूण सकनी के मार्गदर्शन में किया गया।अभियान के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविरों में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र और ब्रम्हास्त्र जैसे जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर उनके उपयोग और लाभ बताए गए। अधिकारियों ने किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के तरीके भी समझाए। जिले में अभियान के लिए चार टीमों का गठन किया गया और कुल 96 शिविर लगाए गए। कृषि रथ के जरिए प्रतिदिन आठ गांवों में पहुंचकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी गई।शिविरों में एग्रीस्टेक पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान समृद्धि योजना, सौर सुजला योजना, राष्ट्रीय ऑयलपाम मिशन, मत्स्य संपदा योजना और डेयरी विकास योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है।

किसानों को बताए प्राकृतिक खेती के फायदे

शिविरों में किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया। जैविक उत्पादों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, लागत घटाने और बेहतर उत्पादन लेने के उपाय बताए गए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।